



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 203]
No. 203]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 23, 2007/श्रावण 1, 1929
NEW DELHI, MONDAY, JULY 23, 2007/SRAVANA 1, 1929

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2007

अंतिम जांच परिणाम

विषय : चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पैरासीटामॉल के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा ।

सं. 15/20/2006-डीजीएडी.—1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए;

(क) पृष्ठभूमि

2. यतः उपर्युक्त नियमावली को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतदपरचात् प्राधिकारी कहा गया है) ने चीन जन. गण. एवं ताइवान के मूल के अथवा वहां से आयातित पैरासीटामॉल (जिसे एतदपरचात् सम्बद्ध उत्पाद/वस्तु कहा गया है) के कथित पाटन के संबंध में दिनांक 30 जून, 2001 को पाटनरोधी जांच शुरू की थी । प्राधिकारी के दिनांक 16 अप्रैल, 2001 के प्रारम्भिक जांच परिणाम के आधार पर दिनांक 6 सितम्बर, 2001 की अधिसूचना सं. 89/2001-सीमाशुल्क द्वारा सम्बद्ध देशों से सम्बद्ध वस्तुओं के आयातों पर अनन्तिम पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था । प्राधिकारी के अंतिम जांच परिणाम दिनांक 22 जनवरी, 2002 की अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सम्बद्ध देशों से सम्बद्ध वस्तुओं पर दिनांक 27 मार्च, 2002 की अधिसूचना सं. 29/2002-सी.शु. द्वारा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाए गए थे ।

3. और यतः प्राधिकारी द्वारा दिनांक 17 मई, 2005 को प्रकाशित संशोधन अधिसूचना के अनुसरण में ताइवान से पाटनरोधी शुल्क दिनांक 19 जुलाई, 2005 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 67/2005 द्वारा वापस ले लिया गया था ।

4. और यतः मै. श्रीकृष्ण फार्मास्यूटिकल्स लि., हैदराबाद; मै. फार्मसन्स एनल्वेसिक्स प्रा.लि., बडोदरा तथा मै. भारत केमिकल्स लि., मुम्बई जो सम्बद्ध उत्पाद के भरेलू उत्पादन के एक प्रमुख भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं, द्वारा विधिवत् प्रमाणित आवेदन के आधार पर यह जांच करने के लिए कि क्या शुल्क समाप्त कर देने से पाटन व क्षति निरंतर होते रहने अथवा उनकी पुनरावृत्ति सम्भावित है, अधिनियम की धारा 9क(5) के अंतर्गत चीन जन. गण. (जिसे एतदपरचात् सम्बद्ध देश कहा गया है) के मूल के सम्बद्ध उत्पादों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा शुरू की गई थी ।

5. और यतः केन्द्र सरकार द्वारा धारा 9क(5) के अंतर्गत दिनांक 31 अगस्त, 2006 की अधिसूचना सं. 87/2006 द्वारा पाटनरोधी शुल्क को एक वर्ष की अवधि के लिए दिनांक 5 सितम्बर, 2007 तक बढ़ा दिया गया था।

ख. प्रक्रिया

6. निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई है :--

- (i) ऊपर उल्लिखित नियम 5 के उप-नियम (5) के अनुसार प्राधिकारी द्वारा समीक्षा जांच संबंधी कार्यवाही शुरू करने से पूर्व भारत में सम्बद्ध देश के दूतावास को आवेदक से पूर्णतः प्रलेखित आवेदन प्राप्त होने के बारे में अवगत कराया गया।
- (ii) ऊपर उल्लिखित नियम 6 के उप-नियम (2) के अनुसरण में प्राधिकारी द्वारा उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना की एक प्रति ज्ञात निर्यातकों, उत्पादकों, आयातकों, उद्योग एसोसिएशनों, सम्बद्ध देश के दूतावास तथा आवेदक को भिजवाई गई और उन्हें अपने विचार लिखित में अवगत कराने का अवसर दिया गया।
- (iii) ऊपर उल्लिखित नियम 6 के उप-नियम (3) के अनुसार बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार प्रदान करने के उद्देश्य से प्राधिकारी द्वारा सभी ज्ञात निर्यातकों तथा सम्बद्ध देश के भारत स्थित दूतावास को आवेदन की एक प्रति तथा इसके साथ प्रश्नावली भी भिजवाई गई। यद्यपि जांच शुरुआत के प्रयोजनार्थ सामान्य मूल्य भारत में सम्बद्ध उत्पाद की संरचित उत्पादन लागत के आधार पर माना गया, तथापि प्राधिकारी द्वारा सम्बद्ध देशों से सम्बद्ध वस्तुओं के ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों को सूचित किया गया कि आवेदकों के दावे की जांच यथासंशोधित पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा (7) एवं (8) के आलोक में की जानी प्रस्तावित है। ज्ञात निर्यातकों से अनुरोध किया गया कि वे पैराग्राफ 8 के उप-पैराग्राफ (3) में यथा उल्लिखित आवश्यक सूचना/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करें, ताकि प्राधिकारी सहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों, जो यह प्रदर्शित कर सकते हैं कि वे उपर्युक्त पैराग्राफ में निर्धारित मानदण्डों को संतुष्ट करते हैं, को बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार प्रदान कर सकें।
- (iv) उपर्युक्त नियम 6 के उप-नियम (4) के अनुसरण में प्राधिकारी द्वारा संबंधित प्रश्नावली की एक-एक प्रति सभी ज्ञात निर्यातकों एवं सम्बद्ध देश के भारत स्थित दूतावास को भिजवाई गई।
- (v) सम्बद्ध देश के भारत स्थित दूतावास को भी जांच की शुरुआत के बारे में सूचित किया गया और अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित अवधि में प्रश्नावली के उत्तर भिजवाने की सलाह देने का अनुरोध किया गया।
- (vi) अपेक्षित सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से प्राधिकारी द्वारा सम्बद्ध देश के निम्नलिखित निर्यातकों को प्रश्नावलियाँ भिजवाई गई :--
 - एनहुई बायी केमिकल कं. लि., 379 हुआईबिन रोड, एनहुई
 - कानलर फार्मास्यूटिकल कार्पोरेशन लि., कॉनलर बिल्डिंग
 - जेजियांग कांगले फार्मास्यूटिकल कं. लि., आरएम 504, 5/एफ, कांगले बिल्डिंग
 - वेनझाऊ फार्मास्यूटिकल फैक्टरी, 112, वेस्ट मांची रोड, वेनझाऊ, जेजियांग प्रान्त
 - चांगशू हुआगांग फार्मास्यूटिकल कं. लि., यूजियांग विलेज, येतांग, टाऊन, चांगशू, जेजियांग्सू
 - हेबेई जिहेंग ग्रुप कं. लि. 58, झोगहुआ स्ट्रीट
 - हेबेई जिहेंग (ग्रुप) फार्मसी कं. लि. नं. 368, जियानशे स्ट्रीट, हेंगशुई सिटी, हेबेई
 - हुआऊ बिगांग एण्टरप्राइजेज ग्रुप कार्पोरेशन, एफ/4 एफ, नॉर्थ एरिया, फू चेंग बिल्डिंग, हुआऊ, जेजियांग
 - झांगजीन फार्मा टियांगजिन जिनजीन फार्मास्यूटिकल्स चेंगलिनझुआंग इंडस्ट्रियल इस्टेट, टियांगजिंग
 - जियांगसू गुओटेल इंटरनेशनल ग्रुप कं. लि. 11 एफ, गुओताई बिल्डिंग, नं. 43, रेनमीन रोड (एम), झानजियांगगांग सिटी जियांगसू प्रांत
 - मै. लियाओयूआन सिटी बाइकांग फार्मास्यूटिकल्स, लियाओयूआन सिटी, जिलीन प्रांत
 किसी भी निर्यातक/आयातक ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर नहीं भिजवाया।
- (vii) आवेदन में सूचीबद्ध विभिन्न आयातकों को जांच शुरुआत अधिसूचना के साथ आयातक प्रश्नावली भिजवाई गई।
 - फ्लेमिंगो फार्मास्यूटिकल्स लि. 18-ए, महल इस्टेट, महाकाली केक्स रोड, मुम्बई-400093
 - ग्रेन्यूल्स इण्डिया लि., 8-2-293/ए/ए/2, रोड नं. 2, बंजारा हिल्स, हैदराबाद

- मेडिच स्टैरीलैब लि., 12, सरस्वती अम्मल स्ट्रीट, बंगलूर-560033
- ग्लो एक्सपोर्ट ट्रेडिंग प्रा. लि. } आईपीसीए हाऊस
- आईपीसीए लैब्स लि. } 63ई, कांदिवली इंडस्ट्रियल एस्टेट
- टेक्नो इकोनॉमिक सर्विसेज प्रा. लि. } कांदिवली वेस्ट
- एगॉग फार्मा } मुम्बई-400067
- माइक्रो लैब्स लि. 92, सिपकोट इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, होसूर-635126
- अजंता फार्मा लि. } प्लॉट नं. ई-28, एमआईडीसी
- शालीना लैब्स प्रा. लि. } फायर ब्रिगेड के सामने, मुम्ब्रा, मुम्बई
- सिप्ला लि., कांदिवली इण्डस्ट्रियल इस्टेट, कांदिवली पश्चिम, मुम्बई-400067
- सीरॉन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स प्रा. लि., एसीएमई प्लाजा, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी पूर्व, मुम्बई-400059
- इण्डिको रेमेडीज लि., 39 सी, प्रथम तल, राज इण्ड. कॉम्प्लेक्स, मिलिटरी रोड, मारोल, अंधेरी पूर्व, मुम्बई-400059
- मनीष फार्मास्युटिकल्स प्रा.लि., 103, शिवाजी नगर, पुणे-411005
- मंगलम ड्रग्स एण्ड आर्गेनिक्स लि. } फोनिक्स हाऊस, तीसरा तल
- मेडोफार्मा } 462, सेनापति बापट मार्ग
- हेल्दी लाइफ फार्मा प्रा.लि. } लोअर परेल
- ग्लो एक्सपोर्ट ट्रेडिंग प्रा.लि. } मुम्बई-400013
- कैडिला फार्मा, ऑक्सफोर्ड चेम्बर्स, बी. पसालकर मार्ग, साकीनाका, मुम्बई-400072
- हिन्दुस्तान टेबलेट्स, मिट स्ट्रीट, नाचरम हाई रोड, हैदराबाद
- मै. इण्डिया लैब्स प्रा.लि., फर्स्ट फ्लोर, एलबी रोड, अडयार, चेन्नई-20
- बाल फार्मा लि., रविकिरण अपार्टमेंट्स, 12 प्लेन स्ट्रीट, बंगलूर-1

तथापि, आयातकों से प्रश्नावली का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

- (viii) व्यापक परिचालनार्थ जांच शुरुआत सूचना फिक्की, सीआईआई, एसोचैम, एक्साइज लॉ टाइम्स आदि को भी भिजवाई गई थीं।
- (ix) पिछले तीन वर्षों तथा जांच अवधि के संबंध में सम्बद्ध वस्तुओं के आयातों के ब्यौरे की व्यवस्था हेतु वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एण्ड एस) से अनुरोध किया गया था।
- (x) पाटन तथा क्षति की जांच में दिनांक 1 अप्रैल, 2005 से 31 मार्च, 2006 (जिसे जांच अवधि अथवा पीओआई भी कहा जाता है) की अवधि शामिल की गई थी।
- (xi) प्राधिकारी ने पाटन एवं परिणामी क्षति के निर्धारण के प्रयोजनार्थ आवश्यक समझी गई समस्त सूचना की माँग की एवं उसका सत्यापन किया। प्राधिकारी ने आवश्यक समझी गई सीमा तक घरेलू उद्योग का मौके पर सत्यापन किया। आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर आधारित सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) के आधार पर इष्टतम उत्पादन लागत और भारत में संबद्ध वस्तुओं को बनाने और इनकी बिक्री करने की लागत का परिकलन करने के लिए घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत का विश्लेषण भी किया गया था ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।
- (xii) प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने विचार मौखिक रूप से प्रकट करने का अवसर प्रदान करने के लिए दिनांक 27 अप्रैल, 2007 को एक सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की जिसमें घरेलू उद्योग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। सार्वजनिक सुनवाई में उपस्थित पक्षकारों से मौखिक रूप से प्रकट किए गए विचारों को लिखित रूप से प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने प्राप्त लिखित प्रस्तुतीकरणों पर इस जांच परिणाम में विचार किया है।

- (xiii) प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंश उनके द्वारा रखी गयी सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध रखे और उसे हितबद्ध पार्टियों के निरीक्षण हेतु खुला रखा।
- (xiv) **** से इस अधिसूचना में हितबद्ध पार्टियों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का पता चलता है और प्राधिकारी ने नियमानुसार उसे गोपनीय ही माना है।

ग. विचाराधीन उत्पाद एवं “समान वस्तु”

7. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद मूल जांच में यथापरिभाषित चीन जन. गण. के मूल का अथवा वहाँ से निर्यातित पैरासिटामॉल है, जिसे एसिया माइनोफेन (जिसे एतदपश्चात् संबद्ध वस्तु कहा गया है) के नाम से भी जाना जाता है। यह एक गंधहीन सफेद पाउडर है जिसका रासायनिक सूत्र $C_8H_9NO_2$ होता है। पैरासिटामॉल पीड़ानाशक तथा ज्वरनाशक विशेषताओं वाला एक थोक भेषज सक्रिय घटक है जिसका प्रयोग ज्वर, सिरदर्द, सामान्य पीड़ा एवं दर्द से राहत के लिए पाऊडर, दाने, सुई या टैब्लेट्स के रूप में कई भेषज फार्मूलेशन्स में किया जाता है।

8. इस उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 29 “कार्बनिक रसायनों” की श्रेणी में उप शीर्ष 2922.29 में परिभाषित किया गया है। वर्ष 2002-03 तक यह 2922.2914 के तहत वर्गीकृत था। वर्ष 2003-04 में अप्रैल, 2003 में आईटीसी (सुमेलीकृत प्रणाली) वर्गीकरण में परिवर्तन के साथ कोड को परिवर्तित करके 2922.2933 कर दिया गया था। इस निर्णायक समीक्षा जांच में केवल वही उत्पाद शामिल है जो मूल जांच में था। चूंकि किसी हितबद्ध पक्षकार ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के मुद्दे पर कोई तर्क नहीं दिया है और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु तथा संबद्ध देश से आयातित वस्तु का उपयोग एक-दूसरे के स्थान पर किया जाता है, अतः प्राधिकारी मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु नियम के अर्थ के भीतर समान वस्तु हैं।

घ. घरेलू उद्योग

9. पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा, उसे जारी रखने तथा उसमें सुधार के लिए आवेदन में श्री कृष्णा फार्मास्युटिकल्स, मै. फार्मसन एनालजे सिक्स तथा मै. भरत केमिकल्स द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया गया था। जाँच अवधि के दौरान घरेलू उत्पादन के 54% हिस्से के साथ वे संबद्ध वस्तु के प्रमुख घरेलू उत्पादक हैं और उन्होंने वर्तमान जांच के संगत सूचना उपलब्ध कराई है। यह सूचित किया गया है कि आवेदकों के अलावा संबद्ध उत्पाद के 9 अन्य लघु उत्पादक हैं। जांच की शुरुआत के बाद एक घरेलू उत्पाद अर्थात् मै. पैरा प्रोडक्ट्स ने समस्त संगत सूचना प्रस्तुत की है। एक अन्य उत्पादक, मै. गैन्यूल्स इंडिया लि., समग्र क्षति अवधि में संबद्ध वस्तु के आयातक रहे हैं और इसलिए नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार उन्हें घरेलू उद्योग का हिस्सा नहीं माना गया है। अन्य उत्पादकों ने सूचना उपलब्ध कराने के प्राधिकारी के अनुरोध का उत्तर नहीं दिया। अतः विधिक उपबंधों तथा मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी आवेदक तथा उनके समर्थक (घरेलू उत्पादन में 75% हिस्सा) को नियमों के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग मानते हैं।

ङ पाटन का जारी रहना

10. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क(1)(ग) के अंतर्गत “किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का अर्थ है :

- समान वस्तु के लिए व्यापार की साधारण प्रक्रिया में तुलनीय कीमत जब वस्तु निर्यातक देश या सीमा क्षेत्र में उपभोग के लिए हो जैसा कि उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारण किया गया है; या
- जब निर्यातक देश या सीमा क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की साधारण प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्रियां न हों अथवा जब निर्यातक देश या सीमा क्षेत्र के घरेलू बाजार में बाजार की विशेष स्थिति या बिक्रियों की कम मात्रा के कारण ऐसी बिक्रियाँ से उचित तुलना की अनुमति न मिले, सामान्य मूल्य; या तो

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधि कीमत जब वस्तु निर्यातक देश या सीमा क्षेत्र या किसी उपयुक्त तीसरे देश से निर्यात की गई हो जैसा कि उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारण किया गया है; या

(ख) प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागतों और लाभों के लिए यथोचित वृद्धि के साथ-साथ उद्गम के देश में बिक्रित वस्तु की उत्पादन लागत होगी, जैसा कि उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारण किया गया है;

बशर्ते उद्गम के देश से इतर किसी देश से वस्तु के आयात के मामले में और जहाँ निर्यात के देश के जरिए वस्तु का केवल वाहनान्तरण किया गया हो या जहाँ निर्यात के देश में ऐसी वस्तु का उत्पादन न किया जाता हो या निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत न हो, तो सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम के देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।”

11. प्राधिकारी ने अनुच्छेद 9क(1)(ग) के अनुसार सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ सभी ज्ञात निर्यातकों को प्रश्नावलियाँ भेजीं। किसी भी निर्यातक ने उत्तर नहीं दिया।

ङ 1 चीन जन. गण. हेतु सामान्य मूल्य का निर्धारण

ङ 1.1 घरेलू उद्योग के विचार

12. घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है कि वर्तमान जांच की वर्तमान प्रक्रिया में चीन जन.गण., संबद्ध देश एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है और उसे यूरोपीय आयोग, अमेरिका तथा स्वयं भारत द्वारा भी यही माना गया है। अतः सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी

नियमावली के अनुबंध I के पैरा 7 व 8 के अनुसार किया जाना है। तदनुसार, घरेलू उद्योग ने चीन में सामान्य मूल्य के परिकलन के प्रयोजनार्थ उचित सहोदर देश के रूप में भारत को लिए जाने का प्रस्ताव किया है क्योंकि संबद्ध वस्तु का उत्पादन केवल भारत और चीन में किया जा रहा है। घरेलू उद्योग ने बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों तथा उचित लाभ को शामिल करने के लिए उचित रूप से समायोजित, भारत में उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है।

भारत में कानूनी उपबंध

13. दिनांक 15 जुलाई की अधिसूचना सं. 44/99-सी.शु. (एनटी) (यथासंशोधित) द्वारा शामिल किए गए, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध I के पैरा 7 को निम्नानुसार पढ़ा जाता है :-

"7. गैर-बाजार देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत सहित, सामान्य मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं है, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा"

बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार (एमईटी)

14. दिनांक 4-1-2002 को सी.शु. अधिसूचना सं. 1/2002-सी.शु. (एनटी) के द्वारा जोड़े गए अनुबंध 1 के पैरा 8 को निम्नानुसार पढ़ा जाता है :-

"8. (1) "गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश" शब्द का अर्थ है कि कोई देश जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी लागत अथवा कीमत ढांचे के बाजार सिद्धांतों को लागू नहीं करने वाले के रूप में मानते हैं। जिसके कारण ऐसे देश में पण्य वस्तुओं की बिक्रियां उप-पैराग्राफ 3 में निर्दिष्ट मानदण्डों के अनुसार वस्तुओं के सही मूल्य को दर्शाती है।

(2) यह परिकल्पित किया जाएगा कि कोई देश जिसे जांच के पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी अथवा डब्ल्यू टी ओ के किसी सदस्य के सक्षम प्राधिकारी अथवा डब्ल्यू टी ओ के किसी सदस्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश निर्धारित अथवा माना गया है एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है।

तथापि, बशर्ते गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश या ऐसे देश की संबंधित फर्मों द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी को ऐसी सूचना या साक्ष्य जिससे यह सत्यापित होता हो कि उप-पैराग्राफ (3) में विनिर्दिष्ट मानदण्डों के आधार पर वह देश गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश नहीं है, प्रस्तुत करके ऐसी परिकल्पना का विरोध कर सकते हैं।

(3) निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रत्येक मामले में निम्नलिखित मानदण्ड पर विचार करेंगे कि क्या

(क) प्रौद्योगिकी की कच्ची सामग्रियों की लागत और श्रम, निविष्ट बिक्रियां और निवेश समेत कीमतों, लागतों और निविष्टियों के बारे में ऐसे देश में संबंधित फर्मों का निर्णय ऐसे बाजारी संकेतों के अनुसार किया जाता है जिसमें आपूर्ति और मांग परिलक्षित होती है और इस बारे में राज्य के अधिक हस्तक्षेप के बिना क्या प्रमुख निविष्टियों की लागत बाजार मूल्यों को पर्याप्त रूप से प्रदर्शित करता है,

(ख) इस प्रकार की फर्मों की उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति विशेषकर परिसम्पत्तियों के मूल्य ह्रास, अन्य बट्टे खातों, वस्तु विनिर्भय-व्यापार और ऋणों की प्रतिपूर्ति के माध्यम से भुगतान के संदर्भ में पूर्ववर्ती गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाली प्रणाली से हुई महत्वपूर्ण विकृतियों के अध्यधीन हैं,

(ग) इस प्रकार की फर्मों दिवालियापन और सम्पत्ति कानूनों के अध्यधीन हैं जो फर्मों के प्रचालन की कानूनी निश्चितता और स्थिरता की गारंटी देते हैं, और

(घ) विनिर्भय दर का परिवर्तन ब्याज की दर पर किया जाता है।

तथापि, बशर्ते जहां इस पैराग्राफ में दिए गए मानदण्डों के आधार पर पर्याप्त साक्ष्यों द्वारा लिखित में यह दर्शाया गया हो कि पाटनरोधी जांचाधीन एक या अधिक फर्मों में बाजार संबंधी स्थितियां विद्यमान हैं, प्राधिकारी इस पैराग्राफ में निर्धारित सिद्धांतों के स्थान पर पैरा 1-6 में निर्धारित सिद्धांतों को लागू करेंगे।"

15. चीन के किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने प्राधिकारी द्वारा भेजी गई प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है और न ही किसी हितबद्ध पक्षकार ने अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं।

1.2 सामान्य मूल्य एवं निर्यात कीमत

16. प्राधिकारी यह जानते हैं कि संबद्ध देशों से किसी निर्यातक ने उत्तर नहीं दिया है और याचिकाकर्ताओं ने बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के रूप में भारत की कीमत अथवा परिकलित मूल्य के साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं। निर्यातक के उत्तर के अभाव में प्राधिकारी ने निर्धारित

किया है कि अंतिम जांच के प्रयोजनार्थ भारत औसत उत्पादन लागत, परिवर्तन लागत एवं बिक्री, भारत में घरेलू उद्योग के सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय के साथ-साथ एक उचित लाभ मार्जिन के आधार पर सामान्य मूल्य का परिकलन करना ही एकमात्र उपलब्ध विकल्प है। इस प्रकार परिकलित सामान्य मूल्य*** रुपए अथवा*** डॉ. प्रति कि. ग्रा. है।

पाटन मार्जिन के निर्धारण की पद्धति

ड. 2. निर्यात कीमत

घरेलू उद्योग के विचार

17. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित निवेदन प्रस्तुत किए हैं :

(1) चूंकि चीन के किसी भी उत्पादक/निर्यातकों ने सहयोग नहीं किया है इसलिए प्राधिकारी द्वारा नियमों के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई किया जाना उचित है।

(2) उत्पाद पर लागू वर्तमान पाटनरोधी शुल्क परिवर्तनीय आधार पर लगाया गया है, मूल जांच में निर्धारित की गई संदर्भ कीमत 3.33 डॉलर प्रति कि. ग्रा. थी। क्षति अवधि के प्रथम दो वर्षों में कीमत कटौती नकारात्मक थी और आयात सीमांत थे। यह तीसरे वर्ष में सकारात्मक हो गई और जांच अवधि के दौरान इसमें वृद्धि हुई जिसके परिणामस्वरूप आयातों में अत्यधिक वृद्धि हुई है।

(3) निर्यात कीमत से सही वस्तुस्थिति और अनेक उपभोक्ताओं और व्यापारियों द्वारा आयात किए जा रहे संबद्ध उत्पाद की कीमत प्रदर्शित नहीं होती है। अग्रिम लाइसेंस के तहत उल्लेखनीय शुल्क मुक्त आयात तथा व्यापारियों/पुनः बिक्री करने वाले विक्रेताओं द्वारा शुल्क के भुगतान के पश्चात् भी आयात किए गए हैं। सौदे-वार आंकड़ा विश्लेषण के अनुसार आयात कीमतों में अंतर है। चूंकि उत्पाद विनिर्देशन लगभग अपरिवर्तनीय हैं अतः अत्यधिक कीमत परिवर्तन होने का कोई कारण नहीं है। पाटनरोधी शुल्क केवल तब ही देय होता है यदि सीआईएफ कीमत बेंचमार्क कीमत से कम होती है। अतः उन सभी सौदों में जहां आयातों की पहुंच कीमत बेंचमार्क कीमत से अधिक अथवा उसके बराबर होती है, वे संदिग्ध हैं और उत्पाद की उचित आयात कीमत का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं।

प्राधिकारी द्वारा जांच

18. प्राधिकारी ने संबद्ध उत्पाद के आयातों का विवरण, जिसमें शुल्क मुक्त तथा शुल्क भुगतान पश्चात् किए गए आयातों को अलग-अलग सूचित किया गया हो, मांगा है। तथापि, न तो सीमाशुल्क प्राधिकारी और न ही डीजीसीआईएण्डएस के पास यथा अपेक्षित अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध हैं। अतः ऐसी अलग-अलग सूचना के अभाव में प्राधिकारी ने पाटन मार्जिन तथा कीमत कटौती के परिकलन हेतु आधिकारिक कीमत पर विचार किया है। संबद्ध उत्पाद हेतु भारत को भारत औसत निर्यात कीमत का निर्धारण किया गया है भाड़े, बीमा, कमीशन एवं हैंडलिंग प्रभावी में संतुलित रूप से समायोजन किया गया है। समायोजन पश्चात् भारत औसत निर्यात कीमत का निर्धारण*** अम. डॉ./कि.ग्रा. के रूप में किया गया है तथा कारखाना द्वार निर्यात कीमत*** डॉ./कि. ग्रा. बनती है।

ड. 3. पाटन मार्जिन

19. प्राधिकारी ने परिकलित सामान्य मूल्य तथा उत्पाद हेतु निर्धारित भारत औसत निर्यात कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य तथा कारखाना द्वार स्तर पर निर्यात कीमतों की तुलना करते हुए पाटन मार्जिन का निर्धारण किया है। इस प्रकार निर्धारित भारत औसत समग्र पाटन मार्जिन अत्यधिक तथा न्यूनतम सीमा से अधिक है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :

	रुपए/कि.ग्रा.	डॉ./कि.ग्रा.
परिकलित सामान्य मूल्य	***	***
निर्यात कीमत	***	***
पाटन मार्जिन	***	***
पाटन मार्जिन %	26.58%	

स्रोत: डीजीएडी

च. क्षति एवं कारणात्मक संबंध : क्षति का जारी रहना

च. 1. घरेलू उद्योग के विचार

20. घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि पाटनरोधी शुल्क लागू किए जाने के बावजूद संबद्ध देश से संबद्ध उत्पादों का आयात जारी रहा है। शुल्क लागू किए जाने के प्रथम वर्ष में आयातों की मात्रा में गिरावट आई थी परन्तु फिर भी वह मात्रा काफी बनी रही है। किसी भी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने क्षति के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की है।

21. पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 में निम्नानुसार उल्लेख है :

“क्षति का निर्धारण :

(1) विनिर्दिष्ट देशों से हुए आयातों के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी आगे इस आशय का निष्कर्ष दृढ़ करेगा कि भारत में ऐसी वस्तु के आयात से भारत में स्थापित किसी उद्योग को वास्तविक क्षति होती है अथवा क्षति का खतरा उत्पन्न होता है अथवा भारत में किसी उद्योग को स्थापित करने में वास्तविक बाधा आती है।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी घरेलू उद्योग को हुई क्षति, घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के खतरे, घरेलू उद्योग की स्थापना में आने वाली वास्तविक बाधा और पाटित आयातों एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध का निर्धारण पाटित आयातों की मात्रा समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर इसके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों का परिणामी प्रभाव समेत संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और इन नियमों के अनुबंध II में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार करेंगे।"

22. पाटनरोधी नियमों के अनुबंध II में निम्नानुसार उपबंध किया गया है कि, क्षति के निर्धारण में इन दोनों की तथ्यपरक जांच शामिल होंगी : (क) पाटित आयातों की मात्रा और समान वस्तु की घरेलू बाजार कीमतों पर पाटित आयातों का प्रभाव (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों का परिणामी प्रभाव। नियम के अनुबंध II (ii) में निम्नानुसार प्रावधान है कि :-

(ii) "पाटित आयातों की मात्रा की जांच करते समय उक्त प्राधिकारी इस बात पर विचार करेगा कि क्या कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभावों के संदर्भ में भारत में उत्पादन अथवा खपत की तुलना में अथवा समग्र रूप में पाटित आयातों में पर्याप्त वृद्धि हुई है . . . । निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात पर विचार करेगा कि क्या पाटित आयातों से भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में कीमतों में काफी कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों से अन्यथा काफी हद तक कीमतों में कमी आयी है अथवा कीमतों में वृद्धि होने से रोका गया है, जो अन्यथा काफी हद तक बढ़ गई होती।

आगे नियम के अनुबंध II में यह प्रावधान है कि :-

(iv) पाटित आयातों से संबद्ध घरेलू उद्योग पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच में बिक्री में लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग, प्राकृतिक तथा संभावित गिरावट, घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, वस्तुसूचियों, रोजगार, वेतन, वृद्धि पूंजीगत निवेश प्राप्त करने की क्षमता पर वास्तविक एवं संभावित नकारात्मक प्रभावों सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों तथा संकेतकों का मूल्यांकन शामिल होगा।"

ख. 2. प्राधिकारी द्वारा जांच

23. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के निवेदनों में उठाए गए तर्कों को नोट किया है और इन तर्कों के आलोक में घरेलू उद्योग को हो रही क्षति के जारी रहने के मुद्दे की जांच की है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की संबद्ध वस्तुओं पर पाटित आयातों के मात्रात्मक एवं कीमत प्रभावों तथा कीमत एवं लाभप्रदता पर उनके प्रभाव की जांच की है। पाटन एवं क्षति के बीच क्षति एवं कारणात्मक संबंधों की मौजूदगी, यदि कोई हो, की जांच करने हेतु, चूंकि संबद्ध देश से निर्यातों हेतु एक सकारात्मक पाटन मार्जिन का निर्धारण किया जा चुका है, अतः क्षति विश्लेषण एवं कारणात्मक संबंध की जांच के प्रयोजनार्थ संपूर्ण निर्यातों को पाटित आयात माना गया है।

क. पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव तथा घरेलू उद्योग पर उसका प्रभाव
आयात संबंधी आंकड़े

24. जांच शुरूआत के पश्चात्, डीजीसीआई एण्ड एस (एक गौण स्रोत) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना से पता चलता है कि उत्पाद को वर्ष 2002-2003 तक सीमाशुल्क वर्गीकरण 2922.2914 तथा उसके पश्चात् 2922.2938 के तहत सूचित किया गया है। कोड में यह परिवर्तन, अप्रैल, 2003 में आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण में परिवर्तन के कारण किया गया है। चूंकि उत्पाद का विवरण केवल सांकेतिक है इसलिए संबद्ध उत्पाद के सभी आयातों को, उनके वर्गीकरण की परवाह न करते हुए मात्रा, मूल्य एवं औसत आयात कीमत के निर्धारण के प्रयोजनार्थ शामिल किया गया है। आंकड़ों के विश्लेषण से प्रदर्शित होता है कि वर्तमान में उत्पाद आयातों का एक बड़ा हिस्सा संबद्ध देश से आता है। जैसा कि निम्नानुसार उल्लिखित है :-

पैरासिटामॉल के आयात

आयात	2002-2003	2003-2004	2004-2005	जांच अवधि
कुल उत्पाद आयात				
मात्रा (मी. टन)	1514.93	1733.01	2131.55	6209.32
मूल्य (लाख रुपए)	1525.83	1793.97	2527.40	8608.62
कीमत/कि.ग्रा.	100.72	103.52	118.57	138.64
चीन जन. गण. से आयात				
मात्रा (मी. टन)	696.00	945.00	1557.65	6204.62
मूल्य (लाख रुपए)	631.01	924.95	1856.52	8586.78
कीमत/कि.ग्रा.	90.66	97.88	119.19	138.39
कुल आयातों में हिस्सा	45.9%	54.5%	73.1%	99.9%
अन्य देशों से आयात				
मात्रा (मी. टन)	818.93	788.01	573.90	4.70
मूल्य (लाख रुपए)	894.83	869.02	670.87	21.84
कीमत/कि.ग्रा.	109.27	110.28	116.90	464.67
स्रोत: डीजीसीआईएस				

25. प्राधिकारी ने पाया है कि संबद्ध देश से आयात जो आधार वर्ष 2002-2003 में कुल संबद्ध उत्पाद आयातों का 46 प्रतिशत थे, बाद में बढ़कर क्रमशः 55 प्रतिशत, 73 प्रतिशत और 99.9 प्रतिशत हो गए, जिसका अर्थ यह है कि संबद्ध देशों से आयातों के कारण अन्य देशों अर्थात् अमरीका, स्विट्जरलैंड और यूके के आयात धीरे-धीरे कम होते चले गए। पाटन न करने वाले देशों से आयात जो वर्ष 2002-2003 में कुल आयातों का 54 प्रतिशत, थे वर्ष 2004-2005 में इस प्रतिशत का आधा और जांच अवधि में केवल 0.1 प्रतिशत रह गए। संबद्ध देश तथा अन्य देशों से उत्पाद के आयात की औसत सीआईएफ दर के बीच अन्तर 2002-2003 में 18 रुपए प्रति कि.ग्रा. से कम होकर 2004-2005 में 2 रुपए/कि.ग्रा. हो गया था जो पुनः "क्राउडिंगआउट" प्रभाव को सिद्ध करता है। जांच अवधि में तीव्र अन्तर के रूप में अन्य देशों से आयातों की कीमत 465 रुपए प्रति कि.ग्रा. के स्तर पर पहुंच गई जो एक विपथन प्रतीत होता है।

मांग का आकलन

26. संबद्ध वस्तु की घरेलू खपत/मांग के परिकलन के लिए प्राधिकारी ने भारत में कुल आयातों में घरेलू उद्योग और अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री मात्रा को जोड़ा था।

मापदण्ड (मी. टन में)	2002-2003	2003-2004	2004-2005	(जांच अवधि)
घरेलू उद्योग की बिक्री	8223	10343	10475	10845
अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री	6200	6200	6200	7100
कुल आयात	1515	1733	2132	6209
मांग	15938	18276	18807	24154
सूचीबद्ध	100	115	118	152
मांग में आयातों का हिस्सा (प्रतिशत)	9.51	9.48	11.33	25.71
प्रवृत्ति	100	100	119	270
सभी घरेलू उत्पादकों का हिस्सा	90.49	90.52	88.67	74.29
प्रवृत्ति	100	100	98	82

स्रोत : घरेलू उद्योग, डीजीसीआईएस

प्राधिकारी ने नोट किया कि भारत में संबद्ध वस्तु के लिए मांग ने सकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित की तथा क्षति अवधि में 52 प्रतिशत और केवल जांच अवधि में लगभग 28 प्रतिशत तक बढ़ी। घरेलू मांग में सभी घरेलू उत्पादकों का हिस्सा आधार वर्ष में 90 प्रतिशत से घटकर जांच अवधि में 74 प्रतिशत हो गया जबकि इसी अवधि के दौरान कुल आयात 9.5 प्रतिशत से लगभग तीन गुना बढ़कर 26 प्रतिशत हो गए।

आयात मात्रा तथा बाजार हिस्सा

27. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में यह जांच की गई थी कि क्या निरपेक्ष रूप से अथवा भारत में उत्पादन या खपत के सापेक्ष पाटित आयातों में कोई उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

मापदण्ड (मी. टन में)	2002-2003	2003-2004	2004-2005	(जांच अवधि)
कुल आयात	1515	1733	2132	6209
चीन से आयात	696	945	1558	6205
सूचीबद्ध	100	136	224	891
चीनी आयात/कुल आयात (%)	45.94	54.53	73.08	99.92

(जांच अवधि)

मापदण्ड (मी. टन में)	2002-2003	2003-2004	2004-2005
घरेलू मांग	15938	18276	18807
निम्नलिखित की घरेलू मांग में % हिस्सा			
(क) चीनी आयात	4.37	5.17	8.28
(ख) अन्य आयात	5.14	4.31	3.05
(ग) घरेलू उद्योग	51.59	56.59	55.70
(घ) अन्य घरेलू उत्पादक	38.90	33.92	32.97
घरेलू उद्योग का उत्पादन	***	***	***
चीनी आयात/घरेलू उद्योग का उत्पादन (%)	100	116	177
			656

स्रोत : घरेलू उद्योग, डीजीसीआईएस

प्राधिकारी ने नोट किया कि संबद्ध देश से आयात 2002-2003 में महज 696 मी. टन से जांच अवधि में निरपेक्ष रूप से बढ़कर 6205 मी. टन हो गए जो यह प्रतिबिंबित करता है कि आधार वर्ष से लगभग आठ गुना वृद्धि हुई। अन्य देशों से आयातों में जांच अवधि के दौरान सिर्फ 0.08% की गिरावट दर्ज की गई। घरेलू मांग के संबंध में संबद्ध देश से आयात 2002-2003 में 4.4% से बढ़कर जांच अवधि में 25.7% हो गए जबकि घरेलू उद्योग के उत्पादन की तुलना में ये 2002-2003 में 100 (सूचीबद्ध) से बढ़कर जांच अवधि में 656 हो गए। इसके अलावा, जैसे-जैसे मांग में चीनी आयातों का हिस्सा बढ़ा घरेलू उद्योग का हिस्सा 2002-2003 से जांच अवधि में लगभग 7% घटा तथा अन्य घरेलू उत्पादकों का हिस्सा आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में लगभग 10% तक घट गया। इसके अतिरिक्त, बाजार हिस्सों में गिरावट की दर 2003-2004 और 2004-2005 के बीच सापेक्षतः धीमी थी। यह जांच अवधि में तीव्र गति से बढ़ी। अतः घरेलू उद्योग के हिस्से में कमी घरेलू प्रतिस्पर्धा के कारण नहीं थी। इसके मद्देनजर प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि संबद्ध देशों से पाटित आयात प्रतिकूल मात्रात्मक प्रभाव दर्शाते हैं।

ख. आयातों पर कीमत प्रभाव

28. इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, घरेलू उद्योग के उत्पादन की भारित औसत लागत, भारित औसत निवल बिक्री वसूली (एनएसआर) और क्षति रहित कीमत (एनआईपी) की संबद्ध देश से आयातों की पहुँच कीमत के साथ तुलना यह जांच करने के लिए की गई है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत के साथ तुलना करने पर पाटित आयातों द्वारा भारी कीमत कटौती की गई है अथवा ऐसे आयातों से कीमतें कम हुई हैं अथवा कीमत में वृद्धि को रोक दिया गया है जो कि अन्यथा उल्लेखनीय स्तर तक बढ़ गई होती।

मापदण्ड (रु./किग्रा.)	2002-03	2003-04	2004-05	जांच अवधि
पहुँच मूल्य	118.77	123.33	144.22	159.15
सूचीबद्ध	100	104	121	134
घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	112	130	145
बिक्री लागत	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	106	125	141
कीमत कटौती*	***	***	***	***
कीमत कटौती %	नकारात्मक	1-5%	0-3%	1-5%

टिप्पणी : *एनएसआर घटा आयातों का पहुँच मूल्य

स्रोत : घरेलू उद्योग, डीजीसीआईएस

29. कीमत कटौती का निर्धारण पाटित आयातों के पहुँच मूल्य की घरेलू उद्योग की भारित औसत निवल बिक्री वसूली (कारखाना द्वार पर) (एनएसआर) के साथ तुलना करके निर्धारित किया गया है जहाँ प्रस्तावित छूट, डिस्काउंट, रियायत तथा प्रदत्त उत्पाद शुल्क को अपवर्जित कर दिया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीनी आयातों का सूचीबद्ध पहुँच मूल्य 2002-2003 से बढ़कर 134 हो गया तथा एनएसआर के मामले में 145 तक बढ़ा किन्तु दानों में बढ़ने की पृवृत्ति प्रदर्शित होती है। पहुँच मूल्य 2003-2004 से जांच अवधि में

एनएसआर की तुलना में कमतर था। जिसके परिणामस्वरूप कीमत कटौती हुई जिसमें 2004-2005 में ठोस रूप से गिरावट आई लेकिन जिसमें जांच अवधि में पुनः वृद्धि हुई। घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत जांच अवधि में ***रु./प्रति किग्रा. निर्धारित की गई है जिसकी तुलना में पहुँच मूल्य 159.15 रूपए प्रति किग्रा. था। कम कीमत पर बिक्री का दायरा (अर्थात्-आयातों का भारित औसत पहुँच मूल्य घटा जांच अवधि के लिए निर्धारित घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत) 1-5% है।

रु./किग्रा. में	
क्षति रहित कीमत	***
पहुँच मूल्य	159.15
कम कीमत पर बिक्री	***
कम कीमत पर बिक्री %	1-5%

स्रोत : डीजीसीआईएस, संगणनाएं

जांच अवधि में कम कीमत पर बिक्री कीमत कटौती से थोड़ी सी अधिक है लेकिन दोनों मात्रात्मक रूप से मामूली है। कीमत न्यूनीकरण का कोई साक्ष्य नहीं मिला है क्योंकि एनएसआर आधार वर्ष को छोड़कर सभी वर्षों में बिक्री की लागत से अधिक बना रहा है।

ग. घरेलू उद्योग की स्थिति : प्रारंभिक टिप्पणियाँ

30. प्राधिकारी ने नोट किया कि याचिकाकर्ता लघु उद्योग की श्रेणी से संबंधित है जो रोजगार-गहन तथा न्यूनतम सावधि निवेश के साथ स्थानिक संवृद्धि का संवर्धन करने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे उद्योगों को कम की गई व्यापार बाधाओं तथा वर्धित मुक्त व्यापार करारों के पश्चात आयातों से घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा का सामना करने में समर्थ बनाने के लिए वृद्धिकारी विआरक्षण (क्षमता का आधुनिकीकरण करने में सीमाओं को हटाना) तथा साख, अवसंरचना विकास, तकनीकी उन्नयन तथा वित्तीय और बाजार सहायता जैसे क्षेत्रों में हस्तक्षेप संबंधी नीतियों को लागू किया गया है।

31. भारत में घरेलू उद्योग पर आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए प्राधिकारी ने ऐसे संकेतकों यथा: उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता, निवल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा तथा मार्जिन आदि जिनका उद्योग की वस्तु स्थिति पर प्रभाव पड़ता है पर उपर्युक्त नियमावली के अनुबंध-II (iv) के अनुसार गौर किया है। यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा हेतु याचिका तीन घरेलू उत्पादकों द्वारा एक समर्थक के साथ संयुक्त रूप से दायर की गई है, जो कुल भारतीय उत्पादन का 75% हिस्सा बनाते हैं। अतः याचिकाकर्ता और समर्थक नियमावली के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग बनाते हैं। अतः निर्दिष्ट प्राधिकारी ने नियमावली के नियम-II के तहत यथा विहित घरेलू उद्योग को हुई क्षति की जांच की है।

बिक्री मात्रा

32. घरेलू उद्योग (डीआई) की बिक्री मात्रा निम्नानुसार है :-

मात्रा (मी. टन में)	2002-03	2003-04	2004-05	जांच अवधि
घरेलू उद्योग-घरेलू बिक्री	8223	10343	10475	10845
सूचीबद्ध	100	126	127	132
घरेलू मांग	15938	18276	18807	24154
सूचीबद्ध	100	115	118	152
मांग में घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा	51.59	56.59	55.70	44.90

स्रोत : घरेलू उद्योग

प्राधिकारी ने नोट किया कि यद्यपि घरेलू उद्योग उत्पाद हेतु कुल मांग के आधे से कम की पूर्ति करता है तथापि इसकी बिक्री मात्रा में संबद्ध वस्तु की मांग में वृद्धि के साथ समवर्ती रूप से जांच अवधि तक स्थायी रूप से वृद्धि हुई है। जिसकी गति में जांच अवधि के दौरान तेजी आई है किन्तु उद्योग बढ़ी हुई मांग, जो आधार वर्ष में घरेलू बिक्री के लिए 32 के गुणक की तुलना में 52 के गुणक तक बढ़ी, का पूरा लाभ उठाने में असमर्थ रहा। भारी बाजार हिस्सा, संबद्ध देश के आयात की तरफ गंवा दिया गया है।

लाभ :

33. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता की स्थिति निम्नानुसार है।

मापदण्ड (लाख रुपए में)	2002-03	2003-04	2004-05	जांच अवधि
लाभ/हानि (रु./कि. ग्राम)	***	***	***	***
सूचीबद्ध	-100	201	126	67
घरेलू बिक्री पर लाभ/हानि	***	***	***	***
सूचीबद्ध	-100	253	160	89

**बिक्री कीमत-बिक्री की लागत

स्रोत : घरेलू उद्योग

प्राधिकारी ने पाया कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में घाटे की स्थिति से लाभ की स्थिति में आते हुए वर्ष 2003-04 में आधार वर्ष की तुलना में सुधार हुआ लेकिन वर्ष 2004-05 से यह स्थिति पुनः खराब हो गई क्योंकि संबद्ध उत्पाद के आयातों में घरेलू उत्पादन की तुलना में वृद्धि हुई थी। तथापि, लाभ तब भी सकारात्मक रहे थे हालांकि यह वर्ष 2003-04 में अर्जित लाभ का केवल तीसरा हिस्सा था।

उत्पादकता

34. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की प्रति कर्मचारी उत्पादकता में वर्ष 2004-05 तक बढ़ोतरी हुई और यह जांच अवधि में थोड़ी कम हो गई थी। प्रति कर्मचारी बिक्री में पूरी समयावधि के दौरान वृद्धि प्रदर्शित हुई है।

मानदण्ड	2002-03	2003-04	2004-05	जांच अवधि
घरेलू उद्योग की बिक्रियां (लाख रु. में)	***	***	***	***
कर्मचारियों की सं.	***	***	***	***
उत्पादन (मी. टन)	***	***	***	***
प्रति कर्मचारी बिक्रियां	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	144	164	174
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	119	125	124

स्रोत : घरेलू उद्योग

निवेश पर आय

35. निवल स्थिर परिसम्पत्तियों में लगाई गई पूंजी में आधार वर्ष के बाद से पीओआई में 22 के गुणक में वृद्धि हुई थी यद्यपि अंतरिमकाल में इसमें कमी आई थी। निवेशों से आय जिसमें वर्ष 2002-03 में एक नकारात्मक आंकड़े से वर्ष 2003-04 में दर के 65 गुणा से भी अधिक वृद्धि हुई थी, में पीओआई में इस स्तर के आधे से कम हो गई थी।

मानदण्ड (लाख रु.)	2002-03	2003-04	2004-05	जांच अवधि
पीवीआईटी	***	***	***	***
सूचीबद्ध	-100	-5805	4154	3586
लगाई गई पूंजी (एनएफए)	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	88	96	122
लगाई गई पूंजी पर आय (एनएफए) (%)	***	***	***	***
सूचीबद्ध	-100	6858	4367	2988

स्रोत : घरेलू उद्योग

क्षमता, उत्पादन एवं क्षमता उपयोग

36. घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन एवं क्षमता उपयोग निम्नानुसार रहे हैं :-

मानदण्ड (मी. टन)	2002-03	2003-04	2004-05	जांच अवधि
क्षमता	—	—	12900	12900
सूचीबद्ध	100	105	116	116
उत्पादन	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	117	126	136
क्षमता उपयोग (%)	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	111	109	117
घरेलू मांग	15938	18276	18807	24154
सूचीबद्ध	100	115	118	152

स्रोत : घरेलू उद्योग

घरेलू उद्योग की क्षमता (सूचीबद्ध) में जांच अवधि में 116 तक की वृद्धि हुई थी, तब भी यह संबद्ध उत्पाद की घरेलू मांग के आधे से कम थी इसलिए अन्य घरेलू उत्पादकों को ध्यान में रखने के बाद भी पूर्ति मांग से कम पड़ जाएगी। पीओआई में क्षमता उपयोग में आधार वर्ष में 89 प्रतिशत की तुलना में 93 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी। बढ़ी हुई मांग के आंशिक रूप से आयातों के जरिए और आंशिक रूप से घरेलू उत्पादन बढ़ा कर पूरा किया गया है।

घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

37. संबद्ध देश से आयातों के कारण पीओआई में भारतीय बाजार में सापेक्ष रूप से न्यूनतम स्तर की कीमत कटौती और कम कीमत पर बिकी हुई है।

पाटन मार्जिन की मात्रा

38. संबद्ध देश से उत्पाद आयातों हेतु पाटन मार्जिन जिसका पैरा 19 में परिकलन किया गया है, को पर्याप्त पाया गया है।

मालसूचियाँ

39. घरेलू उद्योग की मालसूची संबंधी स्थिति निम्नानुसार रही है :-

मानदण्ड (मी. टन में)	2002-03	2003-04	2004-05	जांच अवधि
मालसूची का औसत स्टाक	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	91	30	58
बिकी मात्रा	8223	10343	10475	10845
मालसूची/बिकियां %	***	***	***	***
प्रवृत्ति	100	72	24	44

स्रोत : घरेलू उद्योग

प्राधिकारी ने नोट किया है कि मालसूचियों जिनमें वर्ष 2004-05 तक घटती हुई प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई थी, में पीओआई के दौरान वृद्धि हुई थी हालांकि वे 2002-2003 में मालसूचियों से कम थी। बिक्रियों की मालसूची का प्रतिशत क्षति अवधि के दौरान 2.5% के बीच था।

नकदी प्रवाह एवं नकद लाभ

40. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की नकदी प्रवाह की स्थिति की जांच की है जो निम्नलिखित तालिका में दी गई है।

मानदण्ड (लाख रुपए में)	2002-03	2003-04	2004-05	जांच अवधि
पीबीटी	***	***	***	***
सूचीबद्ध	-100	253	160	89
ब्याज	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	89	86	127
पीबीआईटी	***	***	***	***

मानदंड (लाख रुपए में)	2002-03	2003-04	2004-05	जांच अवधि
सूचीबद्ध	-100	5805	4154	3586
मूल्य ह्रास	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	95	91	98
नकद लाभ	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	632	478	387

स्रोत : घरेलू उद्योग

वर्ष 2002-2003 और 2003-2004 के बीच नकद लाभ में छः गुणा सुधार हुआ था लेकिन पीओआई के दौरान वर्ष 2003-2004 की तुलना में लगभग 40 प्रतिशत के गुणक की गिरावट हुई थी। कर-पूर्व एवं कर पश्चात लाभ दोनों आधार वर्ष में घाटे की स्थिति से वर्ष 2003-2004 में उच्चतम स्तर पर पहुंच गए थे लेकिन इसके पश्चात इनमें गिरावट आई। ब्याज भुगतानों में 2002-2003 के बाद अन्तरिमकाल में कमी आने के बाद पीओआई में वृद्धि हुई थी।

रोजगार एवं मजदूरी

41. घरेलू उद्योग का रोजगार स्तर निम्नानुसार रहा है :-

मानदंड	2002-03	2003-04	2004-05	जांच अवधि
कर्मचारी (सं.)	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	98	101	110
मजदूरी (लाख रुपए)	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	102	111	121

स्रोत : घरेलू उद्योग

प्राधिकारी ने नोट किया कि घरेलू उद्योग के रोजगार स्तर और मजदूरी में वृद्धि हुई थी। इन मापदंडों से क्षति प्रदर्शित नहीं होती है।

पूंजी जुटाने की क्षमता

42. घरेलू उद्योग द्वारा सामना की गई पूंजी जुटाने की क्षमता से संबंधित किसी समस्या का कोई साक्ष्य प्राधिकारी के समक्ष नहीं रखा गया है।

वृद्धि

43. वृद्धि के विभिन्न मापदंडों की स्थिति निम्नलिखित तालिका में दी गई है :-

वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (%)	2003-04	2004-05	जांच अवधि
1. बिक्री मात्रा	25.78	1.28	3.52
2. इकाई बिक्री कीमत	12.20	15.85	11.40
3. उत्पादन लागत	6.25	17.78	12.50
4. उत्पादन	17.06	7.98	7.47
5. पीबीआईटी	5905.26	-28.44	-13.67
6. नकद लाभ	532.14	-24.34	-19.19
7. बाजार हिस्सा	9.69	-1.58	-19.39
8. आरओआई	6958.33	-36.33	-31.58

स्रोत : घरेलू उद्योग

उपर्युक्त तालिका से पता चलता है कि वित्तीय क्षति संबंधी मापदंडों पर क्षति अवधि के दौरान प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और वे नकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित कर रहे हैं।

(i) घरेलू उद्योग के निष्पादन जिसमें वर्ष 2003-2004 तक पाटनरोधी शुल्क लगाने से सुधार आया था, में पीओआई में लाभ एवं हानि, प्रति कर्मचारी उत्पादकता, लगाई गई पूंजी पर आय, बाजार हिस्से, नकद लाभ, कर पूर्व लाभ आदि के लिहाज से गिरावट आई थी।

(ii) आयातों के परिणामस्वरूप न्यूनतम कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री हुई थी।

घ.3 अन्य ज्ञात कारक एवं कारणात्मक संबंध

44. घरेलू उद्योग को हुई क्षति के कारण संबंधी अपने निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए और पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.5 और यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के नियम 11 के अंतर्गत अनुबंध-II के पैरा (v) के अनुसार प्राधिकारी ने सभी ज्ञात कारकों के प्रभाव और घरेलू उद्योग की स्थिति पर पड़े उनके परिणामों की जांच की थी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन अन्य कारकों द्वारा हुई संभावित क्षति के लिए पाटित आयात जिम्मेदार नहीं थे, पाटित आयातों से इतर ज्ञात कारकों जिनसे उसी समय घरेलू उद्योग का क्षति पहुंच सकती थी, की भी जांच की गई थी।

अन्य कारकों का प्रभाव

(क) मांग में संकुचन या खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन

45. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन अवधि के दौरान समग्र मांग में कोई संकुचन नहीं हुआ है। इसके विपरीत क्षति अवधि के दौरान समग्र मांग में भारी वृद्धि है। प्राधिकारी का यह भी निष्कर्ष है कि खपत की प्रवृत्ति में कोई खाम परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ख) अन्य स्रोतों से आयातों की मात्रा एवं कीमतें

46. उपलब्ध सूचना के अनुसार क्षति जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश से इतर देशों के मूल के संबंधित उत्पाद की कुल आयात मात्रा में गिरावट आई और जांच अवधि में यह केवल 0.1 प्रतिशत थी। अतः घरेलू उद्योग पर अन्य देशों से आयातों का प्रभाव कम हुआ है।

(ग) व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं और विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा

47. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि घरेलू बाजार में संबद्ध उत्पाद के अन्य लघु उत्पादक भी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं तथापि उनके हिस्से में घरेलू उद्योग के हिस्से से अधिक गिरावट आई है। संबद्ध देश से पाटित आयात संबद्ध वस्तु के एक ही बाजार में घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु के साथ सीधी प्रतिस्पर्धा करते हैं। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि आयातित उत्पाद की बिक्री घरेलू रूप से उत्पादित संबद्ध वस्तुओं के समान वाणिज्यिक ग्रेडों और विनिर्देशनों की मांग को पूरा करने के लिए की जाती है तथा आयातित और घरेलू रूप से उत्पादित संबद्ध वस्तु समान वस्तुएं हैं और इनका उपयोग समान अनुप्रयोगों/अंतिम प्रयोग हेतु होता है।

(घ) प्रौद्योगिकी में विकास, घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन और उत्पादकता

48. प्रौद्योगिकी में विकास, घरेलू उद्योग को हुई क्षति का संगत कारक नहीं है। जहां तक घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन का संबंध है प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की कुल बिक्रियों में ऐसे निर्यातों का काफी महत्वपूर्ण हिस्सा बनता है। इसके अलावा विभिन्न आर्थिक संकेतकों के संबंध में निष्पादन का निर्धारण केवल घरेलू बिक्रियों के संदर्भ में किया गया है।

49. जहां तक उत्पादकता में सुधार का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन अवधि के दौरान प्रति वर्ष प्रति कर्मचारी उत्पादन के रूप में मापित उत्पादकता में क्षति अवधि के दौरान कुछ सुधार हुआ है और जांच अवधि के दौरान इसमें थोड़ी गिरावट आई है। इस प्रकार प्राधिकारी मानते हैं कि उत्पादकता वस्तुतः घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं है।

घ.4 कारण निर्धारण संबंधी निष्कर्ष

50. पाटित आयातों की मात्रा में भारी वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में भारी गिरावट आई है। पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार हुआ था। परन्तु 2003-04 से संबद्ध देश से पाटित आयातों की मात्रा में वृद्धि के कारण कुछ मापदंडों में पुनः विकृति हुई है।

51. अतः प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि संबद्ध देशों के मूल के पाटित आयातों से पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 और पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.5 के अर्थों के भीतर घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

क्षति मार्जिन की मात्रा

52. क्षति मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ संबद्ध वस्तुओं के पहुंच मूल्य के निर्धारण के लिए डी जी सी आई एण्ड एस के आयात आँकड़ों का प्रयोग किया गया है। क्षतिरहित कीमत का परिकलन याचिकाकर्ता की समर्थक इकाई द्वारा प्रथम आँकड़ों सहित घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त

लागत निर्धारण संबंधी सूचना के विश्लेषण और जाँच के बाद किया गया है। क्षति रहित मार्जिन के परिकलन के लिए प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार निर्धारित क्षतिरहित कीमत की तुलना पहुँच मूल्य के साथ की गई है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :

क्षति मार्जिन परिकलन (रुपये/कि. ग्रा. में)

क्षति रहित कीमत	पहुँच मूल्य	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन
***	159.15	***	1-5%

ज. पाटन और क्षति के जारी रहने की संभावना

53. अधिनियम की धारा 9 क के अनुसार समाप्ति समीक्षा में प्राधिकारी के लिए यह अपेक्षित है कि वे इस बात की जाँच करें कि क्या शुल्क हटाये जाने से पाटन और क्षति जारी रहेंगे या उनकी पुनरावृत्ति होगी।

ज. 1 घरेलू उद्योग के विचार

54. घरेलू उद्योग ने निम्नानुसार अनुरोध किया है :-

(i) पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद भी चीनी निर्यातकों ने पाटन जारी रखा है और वह भी बढ़ी हुई मात्रा में। यदि शुल्क हटाया जाता है तो इसमें और वृद्धि ही होगी।

(ii) मूल जाँच के समय और इस समय प्रचलित मापदंडों/परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पाटन मार्जिन न केवल निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है बल्कि काफी अधिक है। मूल जाँच के समय प्रचलित परिस्थितियाँ अर्थात् पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बाद भी पाटन का जारी रहना, चीन में उत्पादकों के पास अधिशेष क्षमता, तीसरे देश के बाजारों को भारी मात्रा का निर्यात की मौजूदगी वर्तमान जाँच में भी जारी है।

(iii) भारत को निर्यात की कीमत पाटन के जारी रहने की ओर संकेत करती है। पहुँच मूल्य के स्तर पर (पाटनरोधी शुल्क के बिना) भारी कीमत कटौती हुई है। इस प्रकार यदि शुल्क हटाया जाता है तो भारतीय कीमतें चीनी उत्पादकों के लिए अत्यंत आकर्षक होंगी।

(iv) चीन विश्व भर में अन्य देशों को भारी मात्रा का निर्यात करता है और वह भी भारत में कीमत से कम कीमतों पर। शुल्क हटाए जाने पर बेहतर प्राप्तियों के लिए ये निर्यात गंतव्य बदलकर भारत हो जाएगा जिससे पाटन जारी रहेगा और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति होगी।

(v) संबद्ध देश में निर्यातकों ने 64,000 मी. टन की क्षमता का निर्माण किया है जो उनकी घरेलू माँग से काफी अधिक है।

(vi) मूल और वर्तमान जाँच में परिकलित पाटन मार्जिन का स्तर पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने की स्थिति में संभावित पाटन का संकेतक है। वर्तमान जाँच में पाटन मार्जिन काफी अधिक है।

जाँच	पाटन मार्जिन %	आयात (मी.टन)
पूर्ववर्ती	47.30	1372.39
वर्तमान	26.90	6486.55

(vii) पूर्ववर्ती और वर्तमान क्षति अवधियों में आयातों की मात्रा निम्नानुसार है :-

पूर्ववर्ती मामला	आयात (मी.टन)	वर्तमान (आई बी आई एस)	आयात (मी. टन)
1997-98	888	2002-03	1130
1998-99	1162	2003-04	1767
1999-00	1168	2004-05	2754
अप्रैल-सितम्बर, 00	656	2005-06	5417

ज. 2 प्राधिकारी द्वारा जाँच

55. प्राधिकारी ने नोट किया कि संबद्ध देश से आयातों की मात्रा में जाँच अवधि में जबरदस्त उछाल आया है और यह कि वर्तमान जाँच में भी पाटन मार्जिन काफी अधिक है। प्राधिकारी ने यह भी देखा है कि डी जी सी आई एस के अलग-अलग सौदावार आयात आँकड़ों में निर्यात कीमतों में काफी अंतर है, परन्तु भारत औसत पहुँच मूल्य के स्तर पर कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री मामूली रही है और कीमतों में कोई न्यूनीकरण नहीं हुआ है। प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने से आयातों में वृद्धि होगी और इससे घरेलू उद्योग के निष्पादन संबंधी सभी मापदंडों पर प्रभाव पड़ेगा।

ई. भारतीय उद्योग का हित

56. पाटनरोधी शुल्क लगाने का उद्देश्य सामान्य तौर पर पाटन की अनुचित व्यापार प्रक्रिया के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि देश के हित में भारतीय बाजार में मुक्त एवं उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति बहाल की जा सके। यद्यपि पाटनरोधी शुल्क से संबद्ध वस्तु के प्रयोग से विनिर्मित उत्पादों के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं और इस प्रकार उनकी सापेक्ष प्रतिस्पर्धात्मकता पर कुछ प्रभाव पड़

सकता है तथापि इन्हें लागू किए जाने से संबद्ध देश से होने वाले आयात किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होंगे और इस प्रकार इससे उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अ. निष्कर्ष

57. उठाए गए मुद्दों की जांच के बाद और वर्तमान पाटन और क्षति के विश्लेषण तथा पाटन के जारी रहने/उसकी पुनरावृत्ति की संभावना के विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि:

(i) चीन जन गण से संबद्ध वस्तुओं ने इनके सामान्य मूल्य से कम पर भारत में प्रवेश किया है और चीन से आयातित संबद्ध वस्तुओं का पाटन मार्जिन काफी अधिक है और निर्धारित न्यूनतम सीमा से ज्यादा है।

(ii) यदि शुल्क हटाए जाते हैं तो चीन से पाटन के जारी रहने की संभावना है।

(iii) पाटन आयातों के कारण घरेलू उद्योग को इस समय भी मामूली वास्तविक क्षति जारी है और यदि शुल्कों को हटाया जाता है तो घरेलू उद्योग की क्षति जारी रहने की संभावना है।

(iv) अतः पाटन की क्षतिपूर्ति हेतु चीन के मूल की अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तु के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क को लागू रखना आवश्यक है।

58. प्राधिकारी की राय है कि संबद्ध देश से आयातों के विरुद्ध इस उपाय को जारी रखना आवश्यक है। तथापि उस देश से पाटन के वर्तमान स्तर और घरेलू उद्योग को हुई क्षति पर विचार करते हुए प्राधिकारी की यह राय है कि लागू उपायों में संशोधन करने की जरूरत है। अतः प्राधिकारी अधिनियम की धारा 9 क (5) के अनुसार इसके अंतर्गत वर्णित पद्धति एवं ढंग से संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क को लागू रखने की सिफारिश करना आवश्यक समझते हैं।

59. अपेक्षाकृत कम शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने की दृष्टि से इस मामले में क्षति मार्जिन जो पाटन के मार्जिन से कम है, के बराबर के निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को लागू रखने की सिफारिश करते हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि मूल जाँच में लगाया गया शुल्क भिन्न-भिन्न शुल्क आधार पर था परन्तु अब वह इस उत्पाद की कीमत में घट-बढ़ के मद्देनजर निश्चित आधार पर पाटनरोधी शुल्क लगाने को उचित समझते हैं। तदनुसार, प्राधिकारी चीन जन गण के मूल की अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के सभी आयातों पर केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से 3320 रुपये प्रति मी. टन का निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने की सिफारिश करते हैं, जैसा कि निम्नांकित तालिका के कालम 9 में दर्शाया गया है।

क्र. सं.	उपशीर्ष/टैरिफ मक	वस्तुओं का विवरण	बिनिर्देशन	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	माप की इकाई	मुद्रा
1.	2922.29.33	पैरासीटमोल	सभी ग्रेड	चीन जन. गण.	चीन जन. गण.	कोई	कोई	3320	मी टन	आई एन आर
2.	-वही-	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. से इतर कोई देश	कोई	कोई	3320	मी टन	आई एन आर
3.	-वही-	-वही-	-वही-	चीन जन. गण. से इतर कोई देश	चीन जन. गण.	कोई	कोई	3320	मी टन	आई एन आर

ट. आगे की प्रक्रिया

60. इस सिफारिश के आधार पर केन्द्र सरकार के आदेश के विरुद्ध कोई अपील उपर्युक्त अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

61. प्राधिकारी इस निश्चयात्मक उपाय को जारी रखने, इसमें परिवर्तन करने या इसको समाप्त करने, जैसा इसमें अनुशंसित है, की आवश्यकता की इस अधिनियम के संगत प्रावधानों और इस संबंध में समय-समय पर जारी सार्वजनिक सूचनाओं के अनुसार आवधिक रूप से समीक्षा कर सकते हैं। प्राधिकारी द्वारा ऐसी समीक्षा के लिए कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा, यदि यह अनुरोध किसी हितबद्ध पक्षीकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ निर्धारित समय-सीमा के भीतर नहीं किया जाता है।

आर. गोपालन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE-GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd July, 2007

FINAL FINDINGS

Subject: Sunset Review of the definitive anti-dumping duty on imports of Paracetamol originating in/exported from China PR.

No. 15/20/2006-DGAD.— Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules (hereinafter also referred as Rules), 1995, thereof;

A. BACKGROUND

2. Whereas, having regard to above Rules, the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) initiated anti-dumping investigation on 30th January, 2001 into alleged dumping of Paracetamol (hereinafter referred to as subject product/goods) originating in/exported from China PR and Taiwan. Provisional anti-dumping duties were imposed on imports of the subject goods from the subject countries *vide* customs Notification No. 89/2001-Customs dated 6th September, 2001, based on the preliminary findings of the Authority dated 16th April, 2001. The final findings of the Authority were published *vide* Notification of 22nd January, 2002 and definitive anti dumping duties were imposed on the subject goods from the subject countries *vide* Notification No. 29/2002-Customs dated 27th March, 2002.

3. And whereas, pursuant to the amendment notification published by the Authority dated 17th May 2005, anti-dumping duty was withdrawn from Taiwan *vide* Customs Notification No. 67/2005 dated 19th July, 2005.

4. And whereas, on the basis of a duly substantiated application filed by M/s. Sri Krishna Pharmaceuticals Ltd., Hyderabad, M/s. Farmson Analgesics Pvt. Ltd., Vadodara and M/s. Bharat Chemicals Ltd., Mumbai representing a major proportion of the domestic production of the subject product, the Designated Authority initiated sunset review of the Anti-Dumping Duty on imports of the subject product originating from China PR (hereinafter also referred to as subject country) *vide* notification dated 25th July, 2006 under section 9A (5) of the Act, to examine whether the expiry of the duty would lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

5. And whereas, *vide* notification No. 87/2006 dated 31st August, 2006 the definitive duties were extended by the Central Government under Section 9A (5) for a period of one year up to 5th September, 2007.

B. PROCEDURE

6. The procedure described below has been followed:—

- (i) As per sub-rule (5) of Rule 5 *supra*, the Authority notified the Embassy of subject country in India about the receipt of fully documented application from the applicant before proceeding to initiate the review investigation;
- (ii) In accordance with sub-rule (2) of the Rule 6 *supra*, the Authority forwarded copy of the said public notice to the known exporting producers, importers, industry associations, the Embassy of the country concerned and to the applicants and gave them an opportunity to make their views known in writing.
- (iii) As per sub-rule (3) of Rule 6 *supra*, the Authority provided a copy of the application to all the known exporters and the Embassy of subject country in India, together with a questionnaire for according market economy treatment. While for the purpose of initiation, the normal value was considered based on the constructed cost of production of the subject product in India, the Authority informed the known exporters/producers of the subject goods from the subject country that it proposed to examine the claim of the applicants in the light of paras (7) & (8) of Annexure-I of the Anti-Dumping Rules as amended. The known exporters were requested to furnish necessary information/sufficient evidence as mentioned in sub-paragraph (3) of paragraph 8 to enable the Authority to consider grant of market economy treatment to cooperating exporters/producers who could demonstrate that they satisfied the criteria stipulated in the said paragraph.
- (iv) According to sub-rule (4) of Rule 6 *supra*, the Authority provided a copy of the relevant questionnaire to all the known exporters and the Embassy of subject country in India and other interested parties.
- (v) The Embassy of subject country in New Delhi was also informed about the initiation of investigation and requested to advise the exporters/producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time.

- (vi) The Authority sent questionnaires, to elicit relevant information, to the following known exporters from the subject country.
- * Anhui Bayi Chemical Industry Co. Ltd., 379 Huaibin Road, Anhui.
 - * Conler Pharmaceutical Corporation Ltd., Conler Building.
 - * Zhejiang Kangle Pharmaceutical Co. Ltd., RM 504, 5/F Kangle Building
 - * Wenzhou Pharmaceutical Factory, 112 West Ma'anchi Road, Wenzhou, Zhejiang Province.
 - * Changshu Huagang Pharmaceutial Co. Ltd., Yuxiang Village, Yetang Town, Changshu, Jiangsu.
 - * Hebei Jiheng Group Co. Ltd., 58 Zhonghua Street
 - * Hebei Jiheng (Group) Pharmacy Co. Ltd., No. 368, Jianshe Street Hengshui City, Hebei.
 - * Huzhou Beigang Enterprises Group Corp., F/4F, North Area, Fucheng Bldg., Huzhou, Zhejiang.
 - * Zhongxin Pharma Tiangin Xinxin Pharmaceutical, Chenglinzhuang Industrial Estate, Tianjin.
 - * Jiangsu Guotal International Group Co. Ltd., 11/F, Guotai Bldg., No. 41, Renmin Road (M), Zhangjiagang City, Jiangsu Province.
 - * M/s. Liaoyuan City Baikang Pharmaceutical, Liaoyuan City, Jilin Province.
- No exporter/producer responded to the exporter's questionnaire.
- (vii) A copy of initiation notification along with the importers' questionnaire was also sent to the various importers listed in the application.
- * Flamingo Pharmaceuticals Ltd., 18-A, Mahal Estate, Mahakali Caves Road, Mumbai - 400093.
 - * Granules India Ltd., 8-2-293/A/A/2, Road No.2, Banjara Hills, Hyderabad.
 - * Glow Export Trading Pvt. Ltd., IPCA House
 - * IPCA Labs Ltd., 63E, Kandivili Industrial Estate,
 - * Techno Economic Services P. Ltd., Kandivili West.
 - * AGOG Pharma., Mumbai-400067
 - * Medreich Sterilab Ltd., 12 Saraswathi Ammal Street, Bangalore-560033
 - * Micro Labs Ltd., 92 SIPCOT Indl. Complex, Hosur-635 126.
 - * Ajanta Pharma Ltd., Plot No. E 28, MIDC, Opp. Fire BRI
 - * Shalina Labs Pvt. Ltd., Mumbra, Mumbai.
 - * Cipla Ltd., Kandivili Indl. Estate, Kandivili West, Mumbai - 400067.
 - * Ciron Drugs & Pharmaceuticals P. Ltd., ACME Plaza, Andheri Kurla Road, Andheri East, Mumbai 400059.
 - * Indoco Remedies Ltd., 39 C, 1st Floor, Raj Indl. Complex, Military Road, Marol, Andheri East, Mumbai-400059.
 - * Maneesh Pharmaceutical Pvt. Ltd., 103, Shivaji Nagar, Pune-411005.
 - * Mangalam Drugs & Organics Ltd., Phoenix House, 3rd Floor,
 - * Medopharm., 462, Senapati Bapat Marg,
 - * Healthy Life Pharma Pvt. Ltd., Lower Parel
 - * Glow Export Trading Pvt. Ltd., Mumbai-400013
 - * Cadila Pharma, Oxford Chambers, B-Pasalkar Marg, Sakinaka, Mumbai 400072.
 - * Hindustan Tablets, 302, Mint Street, Nacharam High Road, Hyderabad.
 - * May India Labs P. Ltd., 1 st Floor, LB Road, Adyar, Chennai-20.
 - * Bal Pharma Limited., Ravikiran Apartments, 12 Plain ST Bangalore-1.
- However, no response was received to the importers' questionnaire.
- (viii) Copies of initiation notice were also sent to FICCI, CII, ASSOCHAM, Excise Law Times etc., for wider circulation.
- (ix) Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to arrange details of imports of subject goods for the past three years and the period of investigation.

- (x) The investigation of dumping and injury covered the period from 1st April 2005 to 31st March 2006 (Also called the period of investigation or POI). The examination of trends in the context of injury analysis covered the period from 1st April 2002 to the end of POI (also called Injury period).
- (xi) The Authority sought and verified all the information it deemed necessary for the purpose of determination of dumping and resulting injury. The Authority conducted on-the-spot investigation of the domestic industry to the extent considered necessary. The cost of the production of the domestic industry was also analysed to work out the cost of production and the cost to make and sell the subject goods in India on the basis of Generally Accepted Accounting Principles based on the information furnished by the applicants to ascertain if anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- (xii) The Authority held a public hearing on 27th April 2007 to hear the interested parties orally, which was attended by representatives of the domestic industry. The parties attending the public hearing were requested to file written submissions of the views expressed orally. The written submissions received have been considered by Designated Authority in this finding.
- (xiii) The Authority kept available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file maintained by the Authority and kept open for inspection by the interested parties.
- (xiv) ***** in this notification represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules on merits.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND "LIKE" ARTICLE

7. The product under consideration in the present investigation, as defined in the original investigation, is Paracetamol also known as acetaminophen (hereinafter referred to as subject goods), originating in or exported from China PR. It is an odourless white powder, with chemical formula of $C_8H_9NO_2$. Paracetamol is a bulk pharmaceutical active ingredient with analgesic and antipyretic properties, which is used in a number of drug formulations in the form of powder, granules, injectibles and tablets for relief of fever, headaches, minor aches and pains.

8. The product is defined under the category "Organic Chemicals" in Chapter 29 of the Customs Tariff Act, sub-heading 2922.29. Until 2002-03, it was classified under 2922.2914. In 2003-04, with the change in the ITC (Harmonized System) classification from April 2003, the code was altered to 2922.2933. This sunset review investigation covers the product as covered in the original investigation only. As no interested party has extended any argument on the issue of the product under consideration and like article, and the subject goods produced by domestic industry have been used interchangeably with those imported from the subject country, the Authority holds that the subject goods produced by the domestic industry and those being imported from the subject country are like articles within the meaning of the Rules.

D. DOMESTIC INDUSTRY

9. The application for review, continuance and enhancement of anti-dumping duty has been jointly filed by M/s. Sri Krishna Pharmaceuticals, M/s. Farmson Analgesics and M/s. Bharat Chemicals. They are the major domestic producers of the subject goods, with a share of 54% of domestic production in the POI and have provided information relevant to the present investigations. Apart from the applicants, there are reported to be 9 other small-scale producers of the subject product. Subsequent to the initiation, one domestic producer, viz., M/s. Para Products has provided all relevant information. Another producer, M/s. Granules India Ltd has been an importer of the subject product over the entire injury period and therefore, in terms of Rule 2(b) of the Rules, is deemed not to form part of the domestic industry. The remaining other producers did not respond to the Authority's request to provide information. Hence, having regard to the legal provisions and the facts and circumstances of the case, the Authority considers the applicants plus the supporter (accounting for 75% of domestic production) to constitute domestic industry within the meaning of the Rules.

E. CONTINUATION OF DUMPING

10. Under Section 9A (1) (c) of the Customs Tariff Act, 1975,

"Normal value in relation to an article means:

- (i) the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or
- (ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:

- (a) Comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory to an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or
- (b) The cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin."

11. The Authority sent questionnaires to all the known exporters for the purpose of determination of normal value in accordance with Section 9A(1)(c). None responded.

E1 Normal value determination for China PR

E1.1 Views of the domestic industry

12. The domestic industry has submitted that China PR, the subject country under present investigation in the present proceedings, is a Non-Market Economy country and treated as such by the European Commission, the United States and even India. Therefore normal value has to be determined in accordance with the Para 7 and 8 of Annexure I of the Anti Dumping Rules. Accordingly, the domestic industry had proposed India as an appropriate surrogate country for the purpose of calculating normal value in China, as the subject goods are being produced only in India and China. The domestic industry has determined normal value on the basis of the cost of production in India, duly adjusted to include selling, general and administrative expenses and reasonable profit.

Legal provisions in India

13. Para 7 of Annexure I under the Rules, which has been inserted vide notification No. 44/99- Cus (NT) dated 15th July, 1999 (as amended) reads as under:

"7. In case of imports from non-market economy country, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin ..."

Market Economy Treatment (MET)

14. Para 8 of Annexure I—inserted vide Customs Notification No. 1/2002-Cus (N.T.) dated 04-01-2002 reads as follows:

"8.(1) The term "non-market economy country" means any country which the designated authority determines as not operating on market principles of cost or pricing structures, so that sales of merchandise in such country do not reflect the fair value of the merchandise, in accordance with the criteria specified in sub-paragraph (3).

(2) There shall be a presumption that any country that has been determined to be, or has been treated as a non-market economy country for the purpose of an anti dumping investigation by the designated authority or by the Competent Authority of any WTO member country during the three year period preceding the investigation is a non-market economy country.

Provided, however, that a non-market economy country or the concerned firms from such country may rebut such a presumption by providing information and evidence to the designated authority that establishes that such country is not a non-market economy country on the basis of criteria specified in sub-paragraph (3).

(3) The designated authority shall consider in each case the following criteria as to whether:

(a) the decisions of concerned firms in such country regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment, are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values;

(b) the production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts;

(c) such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms, and

(d) the exchange rate conversions are carried out at the market rate;

Provided, however, that where it is shown by sufficient evidence in writing on the basis of the criteria specified in this paragraph that market conditions prevail for one or more such firms subject to anti-dumping investigations, the designated authority may apply the principles set out in paragraphs 1 to 6 instead of the principles set out in this paragraph."

15. No exporter/producer from China responded to the questionnaire sent by the Authority nor did any interested party submit any comments.

E1.2 Normal Value & Export Price

16. The Authority has taken cognizance of the fact that there has been "no response by any exporter from the subject country and that the applicants had provided evidence of price or constructed value in India as a market economy third country. In the absence of exporter response, the Authority has determined that the only option available for the purpose of final findings is to construct the normal value by taking into account the weighted average cost of production, conversion costs and selling, general and administrative expenses of the domestic industry in India together with a reasonable margin of profit. The normal value so constructed is Rs. *** or \$ *** per kg.

Methodology for working out dumping margin

E.2 Export Price

Views of the domestic industry

17. The domestic industry has made the following submissions:

- (i) As none of the Chinese producers/exporters have cooperated, the Authority is justified in proceeding on the basis of facts available in accordance with the Rules.
- (ii) The present anti-dumping duty in force on the product is on variable basis, the reference price determined in the original investigation being \$ 3.33 per kg. Price undercutting was negative in the first 2 years of the injury period and imports were limited. It became positive from the third year and increased in the period of investigation, as a consequence of which imports increased very significantly.
- (iii) The export price does not reflect the true state of affairs and the price at which the subject product is being imported by a number of consumers and traders. There are significant duty-free imports under advance licence as also duty paid imports by traders/re-sellers. There are differences in the import prices in transaction-wise data analysis. As product specifications are practically invariant, there is no reason for significant price variations. Anti-dumping duty is payable only if CIF price is below the benchmark price. Thus, all transactions where the landed prices of imports are higher than or equal to the benchmark are suspect and do not represent the true import price of the product.

Examination by the Authority

18. The Authority sought the details of imports of the subject product segregated into duty-free versus duty-paid imports. However, neither the Customs authority nor DGCIS had the data segregated as required. Therefore, in the absence of such segregation, the Authority has taken the official price for calculation of dumping margin and price undercutting. A weighted average export price to India has been determined for the subject product. Adjustments like freight, insurance, commission and handling expenses have been conservatively allowed. The weighted average export price has been taken as US \$ *** per kg. and after adjustments, the ex-works export price comes to \$ *** per kg.

E.3 Dumping margin

19. The Authority has worked out the dumping margin by making a comparison between the normal value and export prices at ex-factory level, based on the constructed normal value and the weighted average export price determined for the product. The weighted average overall dumping margin thus determined is seen to be significant and above minimis, as shown below:

	Rs. / kg.	\$/kg.
Constructed Normal Value	***	***
Export Price	***	***
Dumping Margin	***	***
Dumping Margin %	26.58%	

Source : DGAD.

F. INJURY AND CAUSAL LINK: CONTINUATION OF INJURY

F.1 Views of the domestic industry

20. The domestic industry has argued that despite the imposition of anti-dumping duty, imports of the subject product from the subject country have continued. The volume of imports decreased in the first year after the imposition of duty but continued to remain significant. No other interested party offered any comments on injury.

21. Rule 11 of Anti-dumping Rules reads as follows:

“Determination of Injury:

(1) In the case of imports from specified countries, the designated authority shall record a further finding that import of such article into India causes or threatens material injury to any established industry or materially retards the establishment of any industry in India.

(2) The designated authority shall determine the injury to domestic industry, threat of injury to domestic industry, material retardation to establishment of domestic industry and a causal link between dumped imports and injury, taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on price in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles and in accordance with the principles set out in Annexure II to these rules.”

22. Annexure II to the Rules requires that a determination of injury shall involve an objective examination of both (a) the volume of the dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for like article and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. Annexure II (ii) of the Rules provides as under :—

- (ii) “While examining the volume of dumped imports, the said Authority shall consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India with regard to the effect of the dumped imports on prices... the designated authority shall consider whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree.”

Annexure II to the Rules further provide that

- “(iv) the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.”

F.2 Examination by the Authority

23. The Authority has taken note of the arguments raised by the domestic industry in their submission and examined the issue of continuation of injury to the domestic industry in the light of these arguments. For the purpose of injury analysis, the Authority has examined the volume and price effects of dumped imports on the subject goods on the domestic industry and its effect on the prices and profitability. To examine the existence of injury and causal links between dumping and injury, if any, since a positive dumping margin has been established for the exports from the subject country, the entire exports has been treated as dumped imports for the purpose of injury analysis and causal link examination.

A. Volume effect of dumped imports and impact on domestic industry

Import statistics

24. The information provided by DGCI&S (a secondary source), consequent to the initiation of the investigation, show that the product has been reported under customs classifications 2922.2914 up to 2002-03 and 2922.2933 thereafter, the alteration in the code being due to the change in the ITC (HS) classification in April, 2003. Since the product description is only indicative, all imports of subject goods irrespective of their classification have been included for the purpose of determination of volume, value and average import price. Data analysis shows that bulk of the product imports are from the subject country at present, as below:

Imports of Paracetamol

Imports	2002-03	2003-04	2004-05	POI
Total product imports				
Qty. (MT)	1514.93	1733.01	2131.55	6209.32
Value (Rs. lacs)	1525.83	1793.97	2527.40	8608.62
Price/kg.	100.72	103.52	118.57	138.64
Imports from China PR				
Qty. (MT)	696.00	945.00	1557.65	6204.62
Value (Rs. lacs)	631.01	924.95	1856.52	8586.78
Price/kg.	90.66	97.88	119.19	138.39
Share in total imports	45.9%	54.5%	73.1%	99.9%
Imports from other countries				
Qty. (MT)	818.93	788.01	573.90	4.70
Value (Rs. lacs)	894.83	869.02	670.87	21.84
Price/kg.	109.27	110.28	116.90	464.67

Source: DGCIS.

25. The Authority noticed that imports from the subject country which was 46% of total subject product imports in the base year 2002-03 increased to 55%, 73% and 99.9% respectively in the years thereafter, implying that imports from the subject country crowded out those from other countries, viz., USA, Switzerland and UK. Imports from countries not dumping, which were 54% of total imports in 2002-03, were half this percentage in 2004-05 and merely 0.1 % in the POI. The difference between the average CIF rate of the imports of the product from the subject country and from other countries narrowed from Rs. 18 per kg. in 2002-03 to Rs. 2 per kg. in 2004-05, again testifying to the crowding-out effect. In sharp contrast, in the POI, the price of imports from other countries shot up to Rs. 465 per kg., which appears to be an aberration.

Assessment of demand

26. For the calculation of the domestic consumption/demand of the subject goods, the Authority added the sales volume of the domestic industry and other Indian producers to the total imports into India.

Parameter (in MT)	2002-03	2003-04	2004-05	POI
Sales of Domestic industry	8223	10343	10475	10845
Sales of other domestic producers	6200	6200	6200	7100
Total imports	1515	1733	2132	6209
Demand	15938	18276	18807	24154
Indexed	100	115	118	152
Share of imports in demand (%)	9.51	9.48	11.33	25.71
Trend	100	100	119	270
Share of all domestic producers	90.49	90.52	88.67	74.29
Trend	100	100	98	82

Source: Domestic industry, DGCIS.

The Authority noted that the demand for the subject goods in India showed positive growth and increased by 52% in the injury period and by about 28% in the POI alone. The share of all domestic producers in domestic demand declined from 90% to 74% from the base year to the POI, while that of total imports increased almost three-fold from 9.5% to 26% over the same period.

Import volumes and market share

27. With regard to the volume of the dumped imports, it has been examined whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India.

Parameter (in MT)	2002-03	2003-04	2004-05	POI
Total Imports	1515	1733	2132	6209
Imports from China	696	945	1558	6205
Indexed	100	136	224	891

Parameter (in MT)	2002-03	2003-04	2004-05	POI
Chinese imports/ total imports (%)	45.94	54.53	73.08	99.92
Domestic demand	15938	18276	18807	24154
Percentage share in domestic demand of				
(a) Chinese imports	4.37	5.17	8.28	25.69
(b) other imports	5.14	4.31	3.05	0.02
(c) domestic industry	51.59	56.59	55.70	44.90
(d) other domestic producers	38.90	33.92	32.97	29.39
Domestic industry production	***	***	***	***
Chinese imports/DI production (%)	100	116	177	656

Source: Domestic industry, DGCIS.

The Authority noted that the imports from the subject country increased in absolute terms from just 696 MT in 2002-03 to 6205 MT in the POI, reflecting an almost eight fold increase from the base year. The share of imports from other countries dwindled to merely 0.08% in the POI. In relation to domestic demand, the imports from the subject country increased from 4.4% in 2002-03 to 25.7% in the POI, while relative to domestic industry's production, they increased from 100 (indexed) in 2002-03 to 656 in the POI. Moreover, as the share of Chinese imports in demand increased, that of the domestic industry declined by about 7% from 2002-03 to the POI and of the other domestic producers fell all through by about 10% in the POI compared to the base year. Besides, while the rate of fall in the market shares was relatively slow between 2003-04 and 2004-05, it accentuated steeply in the POI. Hence, the reduction in the domestic industry's share has not been due to domestic competition. In view of this, the Authority has concluded that the dumped imports from the subject country show adverse volume effect.

B. Price effect of imports

28. For the purpose of this analysis, the weighted average cost of production, weighted average Net Sales Realisation (NSR) and the Non-Injurious Price (NIP) of the domestic industry have been compared with the landed price of imports from the subject country to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports compared with the price of the like product in India or whether such imports have depressed the prices or prevented price increases that otherwise would have occurred to a significant degree.

Parameter (Rs./kg.)	2002-03	2003-04	2004-05	POI
Landed Price	118.77	123.33	144.22	159.15
Indexed	100	104	121	134
Net Sales Realization of Domestic industry	***	***	***	***
Indexed	100	112	130	145
Cost of sales	***	***	***	***
Indexed	100	106	125	141
Price undercutting*	***	***	***	***
Price undercutting %	negative	1-5%	0-3%	1"-5%

Note: * NSR minus landed price of imports

Source: Domestic industry, DGCIS.

29. Price undercutting has been determined by comparing the landed value of dumped imports, with the weighted average net sales realisation (ex factory) (NSR) of the domestic industry, where the rebates, discounts, commissions offered and the excise duties paid have been excluded. The Authority notes that the indexed landed value of Chinese imports increased by 134 since 2002-03, and that of NSR increased by 145, but both show a rising trend. The landed value was lower than the NSR in the years 2003-04 to the POI, resulting in price undercutting, which declined substantially in 2004-05 but increased again in the POI. The non-injurious price for the domestic industry has been determined at Rs. *** per kg. in the POI, against which the landed value was Rs. 159.15 per kg. The extent of price under selling (i.e., weighted average landed value of imports less non-injurious price of the domestic industry determined for the POI) is 1-5%.

In Rs./kg	
Non-Injurious Price	***
Landed value	159.15
Price Under-selling	***
Price Under-selling %	1-5%

Source: DGCIS, computations.

Price under-selling in the POI is slightly higher than price under-cutting, but both are marginal in magnitude. There is no evidence of price suppression, as the NSR has remained above the cost of sales in all the years excepting the base year.

C. Situation of the Domestic Industry: Preliminary remarks

30. The Authority noted that the petitioners belonged to the category of small scale industries that are held to be employment-intensive and promoting spatial growth with minimum fixed investment. To enable such industries to face competition in the domestic market from imports following lowered trade barriers and increased free trade agreements, policies of progressive de-reservation (to remove limits on modernising ability) and interventions in fields such as credit, infrastructure development, technical upgradation and fiscal & market support have been put in place.

31. For the examination of the impact of the imports on the domestic industry in India, the Authority considered such indices having a bearing on the state of the industry as production, capacity utilisation, sales quantum, stock, profitability, net sales realisation, the magnitude and margin of dumping, etc. in accordance with Annexure II (iv) of the Rules supra. It is noted that application for review of anti dumping duty has been jointly filed by three domestic producers, with a supporter, who together accounted for 75% of total Indian production. The petitioners and the supporter, therefore, constitute domestic industry within the meaning of the Rules. The Designated Authority therefore, has examined injury to the domestic industry as prescribed under the Rule 11 of the Rules.

Sales Volume

32. Sales volume of the domestic industry (DI) has been as under:

Volume (in MT)	2002-03	2003-04	2004-05	POI
DI- Domestic Sales	8223	10343	10475	10845
Indexed	100	126	127	132
Domestic Demand	15938	18276	18807	24154
Indexed	100	115	118	152
Market share of DI in demand (%)	51.59	56.59	55.70	44.90

Source: Domestic industry.

The Authority noted that though the domestic industry could meet less than half the total demand for the product, its sales volume has consistently increased till the POI, concurrent with the increase in demand of subject goods, the pace of which accelerated in the POI. But the industry was unable to get the full benefit of the increased demand, which rose by a factor of 52 from the base year, against a factor of 32 for domestic sales. Significant market share has been lost to imports from the subject country.

Profits

33. Profitability position of the domestic industry has been as under:

Parameter (in Rs. Lakhs)	2002-03	2003-04	2004-05	POI
Profit/Loss (Rs./Kg.) **	***	***	***	***
Indexed	-100	201	126	67
Profit/Loss on Domestic sales	***	***	***	***
Indexed	-100	253	160	89

** Selling Price - Cost of Sales

Source: Domestic industry.

The Authority observed that profitability of the domestic industry improved in 2003-04 compared to the base year, moving from a situation of loss to one of profits, but the position deteriorated again from 2004-05, as imports of the subject product increased relative to domestic production. Profits, however, still remained positive, though only a third of what had accrued in 2003-04.

Productivity

34. The Authority noted that productivity per employee of the domestic industry increased till 2004-05 and dropped very slightly in the POI. Sales per employee have shown an increase all through.

Parameter	2002-03	2003-04	2004-05	POI
Sales of the DI (Rs. Lakhs)	***	***	***	***
Employees in Nos.	***	***	***	***
Production (MT)	***	***	***	***
Sales per Employee	***	***	***	***
Indexed	100	144	164	174
Productivity per Employee	***	***	***	***
Indexed	100	119	125	124

Source : Domestic industry.

Return on Investment

35. Capital employed in net fixed assets increased by a factor of 22 in the POI since the base year, although it had fallen in the interim. Return on investments which had increased from a negative figure in 2002-03 to over 65 times the rate in 2003-04, dropped in the POI to less than half that level.

Parameter (Rs. Lakhs)	2002-03	2003-04	2004-05	POI
PBIT	***	***	***	***
Indexed	-100	-805	4154	3586
Capital Employed (NFA)	***	***	***	***
Indexed	100	83	96	122
Return on cap. employed (NFA) (%)	***	***	***	***
Indexed	-100	-858	4367	2988

Source : Domestic industry.

Capacity, Production and Capacity Utilization

36. The capacity, production and capacity utilization of the domestic industry has been as under:

Parameter (MT)	2002-03	2003-04	2004-05	POI
Capacity	11100	11700	12900	12900
Indexed	100	105	116	116
Production	***	***	***	***
Indexed	100	117	126	136
Capacity Utilization (%)	***	***	***	***
Indexed	100	111	109	117
Domestic Demand	15938	4276	18807	24154
Indexed	100	115	118	152

Source : Domestic industry.

The domestic industry's capacity (indexed) increased to 116 in the POI, yet was less than half the home demand for the subject product, so that even taking account of other domestic producers, supply would fall short of demand. The capacity utilisation increased in the POI to 93% compared to 80% in the base year. The increased demand has been met partly through imports and partly through increased domestic production.

Factors affecting domestic prices

37. The imports from subject country have led to price under-cutting and price under-selling in the Indian market in the POI, of a relatively minimalist order.

Magnitude of dumping margin

38. The dumping margin for product imports from the subject country computed in para 19 is found to be significant.

Inventories

39. Inventories position with the domestic industry has been as under:

Parameter (in MT)	2002-03	2003-04	2004-05	POI
Average stock of inventory	***	***	***	***
Indexed	100	91	30	58
Sales volume	8223	10343	10475	10845
Inventory/Sales %	***	***	***	***
Trend	100	72	24	44

Source: Domestic industry.

The Authority noted that inventories which had shown a declining trend up to 2004-05 increased in the POI, though they were lower than in 2002-03. The percentage of inventory to sales ranged between 2-5% during the injury period.

Cash Flow and Cash Profit

40. The Authority has examined cash flow situation of the domestic industry, which is given in the following table:

Parameter (in Rs. Lakhs)	2002-03	2003-04	2004-05	POI
PBT	***	***	***	***
Indexed	-100	253	160	89
Interest	***	***	***	***
Indexed	100	89	86	127
PBIT	***	***	***	***
Indexed	-100	5805	4154	3586
Depreciation	***	***	***	***
Indexed	100	95	91	98
Cash profit	***	***	***	***
Indexed	100	632	478	387

Source: Domestic industry.

Cash profits had improved six fold between 2002-03 and 2003-04, but deteriorated by a factor of about 40% during the POI, relative to 2003-04. Both pre- and post-tax profits peaked in 2003-04 from a position of loss in the base year, but dropped off thereafter. Interest payments increased in the POI, after having declined in the interim after 2002-03.

Employment and wages

41. Employment level of the domestic industry has been as under:

Parameter	2002-03	2003-04	2004-05	POI
Employees (No.)	***	***	***	***
Indexed	100	98	101	110
Wages (Rs. Lakhs)	***	***	***	***
Indexed	100	102	111	121

Source : Domestic industry.

The Authority noted that the employment level of the domestic industry had increased and so also wages. These parameters do not reflect injury.

Ability to raise capital

42. No evidence has been placed before the Designated Authority of any problem faced by the domestic industry relating to the ability to raise capital.

Growth

43. Status of various parameters of growth is given in the following table.

Year-to-year growth (%)	2003-04	2004-05	POI
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Sales Volume	25.78	1.28	3.52
2. Unit selling price	12.20	15.85	11.40
3. Cost of production	6.25	17.78	12.50
4. Production	17.06	7.98	7.47
5. PBT	5905.26	-28.44	-13.67
6. Cash profit	532.14	-24.34	-19.19
7. Market Share	9.69	-1.58	-19.39
8. ROI	6958.33	-36.33	-31.58

Source: Domestic industry.

The table above shows that the financial injury parameters have been adversely affected during the injury period and are showing negative growth.

(i) Performance of the domestic industry which had improved with the imposition of anti-dumping duty up to 2003-2004, deteriorated in the POI in terms of profit and loss, productivity per employee, return on capital employed, market share, cash profits, profits before tax, etc.

(ii) Imports resulted in marginal price undercutting and price underselling.

F. 3 Other known factors and causal link

44. In order to reach its conclusions on the cause of the injury suffered by the domestic industry and in accordance with Article 3.5 of Agreement of Anti-dumping and as per para (v) of Annexure II under Rule 11 under Customs Tariff Act as amended, the Authority examined the impact of all known factors and their consequences on the situation of the domestic industry. Known factors other than the dumped imports, which could at the same time have injured the domestic industry, were also examined to ensure that the possible injury caused by these other factors was not attributed to the dumped imports.

Effect of Other factors

(a) Contraction of demand or Changes in the pattern of consumption

45. The Authority notes that there is no contraction in the overall demand during the period under consideration. On the contrary, the overall demand has increased significantly during the injury period. The Authority also concludes that there is no apparent change in the pattern of consumption.

(b) Volume and Prices of imports from other sources

46. According to the available information, the total import volume of the product concerned originating in countries other than the subject country declined over the injury investigation period and was only 0.1 % in the POI. Therefore, the impact of imports of other countries on the domestic industry has reduced.

(c) Trade Restrictive practices of and competition between foreign and domestic producers

47. The Authority notes that though there are other small scale producers of the subject product competing in the domestic market, their share had fallen more than that of the domestic industry. Dumped imports from the subject country compete directly with the subject goods produced by the domestic producers in a single market for the subject goods. The Authority also notes that the imported product is sold to meet the similar commercial grades and specifications as domestically produced subject goods and that the imported and domestically produced subject products are like articles and are used for similar applications/end uses.

(d) Developments in Technology, Export Performance and Productivity of the Domestic Industry

48. Developments in technology are not a relevant factor for the injury to the domestic industry. As for the export performance of the domestic industry, the Authority notes that such exports form a very insignificant part of the total sales of the domestic industry during the injury period. Further, the performance with respect to various economic indicators has been determined with respect to domestic sales only.

49. As regards improvement in productivity, the Authority notes that during the period under consideration, the productivity measured as production per employee per year has rather improved during the injury period and fallen very slightly in the POI. Hence, the Authority holds that the productivity *per se* is not the cause for the injury to the domestic industry.

F. 4 Conclusions on causation

50. Significant increase in the volume of dumped imports has resulted in marked decline in market share of the domestic industry. The imposition of antidumping-duty had resulted in an improvement in the performance of the domestic industry, but some parameters have deteriorated again from 2003-2004, with an increase in volume of dumped imports from the subject country.

51. The Authority, therefore, concludes that the dumped imports originating in the subject country have caused material injury to the domestic industry within the meaning of Rule 11 of Anti-Dumping Rules and Article 3.5 of the Agreement of Anti-Dumping.

Magnitude of Injury Margin

52. Import data from DGCI&S has been used for the determination of landed value of the subject goods for the purpose of determination of injury margin. Non-injurious price has been computed after analysis and scrutiny of the costing information provided by the domestic industry, including the data provided by the unit supporting the petitioners. The non Injurious price so determined by the Authority has been compared with the landed value for computing the injury margin, as shown below:

Injury margin calculations (in Rs/kg)			
Non-Injurious price	Landed value	Injury Margin	IM%
***	159.15	***	1-5%

H. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OF DUMPING AND INJURY

53. Section 9A of the Act requires the Designated Authority, in an expiry review, to examine whether cessation of the duty would lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

H. 1 Views of the domestic industry

54. The domestic industry has submitted as follows:

(i) The Chinese exporters have continued dumping even after the imposition of anti-dumping duty and in increasing volumes. This would only increase if the duties are revoked.

(ii) There are no changes in the parameters/circumstances prevailing at the time of original investigation and at present. Dumping margins are not only more than de-minimis but also significant. Circumstances prevalent at the time of original investigations continue to exist in present investigation, viz., continued dumping even after imposition of the anti-dumping duty, surplus capacities with producers in China, huge volume of exports to third country markets.

(iv) The export price to India is an indicator of the continuation of dumping. At the landed price (without anti-dumping duty), there is significant price undercutting. Hence, if duty is revoked, Indian prices would be extremely attractive to Chinese producers.

(v) China exports significant volume to other countries world-over and at prices lower than the price to India. In the event of duty revocation, these exports would shift to the Indian market to get better realization, leading to continuation of dumping and consequent injury to the domestic industry.

(vi) Exporters in the subject country have built capacities of 64,000 MT, far in excess of their domestic demand.

(vii) The level of dumping margin established in the original and current investigations is an indicator of likely dumping in the event of revocation of anti-dumping duties. Dumping margin in the present investigation is significant.

Investigations	Dumping margin%	Imports (MT)
Previous	47.30	1372.39
Current	26.90	6486.55

(viii) Volume of imports in the previous and current injury periods is as below

Previous case	Imports (MT)	Current (IBIS)	Imports (MT)
1997-98	888	2002-03	1130
1998-99	1162	2003-04	1767
1999-00	1168	2004-05	2754
Apr-Sep 00	656	2005-06	5417

H.2 Examination by the Authority

55. The Authority noted that the volume of the imports from the subject country has recorded a very significant jump in the POI and that the dumping margin in the current investigations also is quite significant. The Authority further observed considerable variation in export prices reflected in individual transaction-wise DGCIS import data, but at the weighted average landed value, price undercutting and underselling have been marginal and there has been no price suppression. The Authority concludes that revocation of anti-dumping duty would result in intensified imports and impact on all performance parameters of the domestic industry.

I. INDIAN INDUSTRY'S INTERESTS

56. The purpose of anti-dumping duties in general is to eliminate injury to the domestic industry caused by the unfair trade practice of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market in the interests of the country. Though anti-dumping duties might affect the price levels of the products manufactured using subject goods and thereby have some impact on their relative competitiveness, their imposition would not restrict imports from the subject country in any way, and, therefore, would not affect the availability of the products to the consumers.

J. CONCLUSIONS

57. After examining the issues raised and based on the analysis of current dumping and injury and likelihood of continuation/recurrence of dumping and injury, the Authority concludes that:

- The subject goods have entered from China PR at less than its normal value and the dumping margins of the subject goods imported from China are substantial and above de minimis
- There is also a likelihood of dumping to continue from China, if the duties are revoked;
- The domestic industry continues to suffer marginal material injury at present due to the dumped imports and the injury to domestic industry is likely to continue, if the duties are revoked;
- Therefore, continued imposition of the anti-dumping duty is warranted against subject goods originating in or exported from China, to offset dumping.

58. The Authority is of the opinion that continuation of the measure is required against imports from the subject country. However, considering the current level of dumping from that country and injury suffered by the domestic industry, the Authority is of the opinion that the measure in force needs to be revised. Therefore, the Authority considers it necessary to recommend continued imposition of the anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject country, in terms of Section 9A(5) of the Act, in the form and manner described hereunder.

59. Having regard to the lesser duty rule, the Authority recommends continued imposition of definitive anti-dumping duty equal to the margin of injury which is lesser than the margin of dumping in this case in order to remove the injury to the domestic industry. The Authority notes the duty in the original investigation was on variable duty basis, but considers it appropriate to impose it on fixed duty basis now in view of the product price fluctuations. Accordingly, the Authority recommends the imposition of definitive anti-dumping duty of Rs. 3320 per MT as indicated in column 9 of the Table below to be imposed from the date of notification to be issued in this regard by the Central Govt. on all imports of subject goods originating in or exported from China PR.

TABLE

S.No.	Sub-Heading, Tariff Item	Description of Goods	Specifications	Country of Origin	Country of Export	Producer	Exporter	Amount	Unit of Measurement	Currency
1.	2922.29.33	Paracetamol	All grades	China PR	China PR	Any	Any	3320	MT	INR
2.	-do-	-do-	-do-	China PR	Any country other than China PR	Any	Any	3320	MT	INR
3.	-do-	-do-	-do-	Any Country other than China PR	China PR	Any	Any	3320	MT	INR

K. FURTHER PROCEDURE

60. Any appeal against the orders of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

61. The Authority may review the need for continuation, modification or termination of the definitive measure as recommended herein from time to time as per the relevant provisions of the Act and public notices issued in this respect from time to time. No request for such a review shall be entertained by the Authority unless the same is filed by an interested party within the time limit stipulated for this purpose.

R. GOPALAN, Designated Authority.